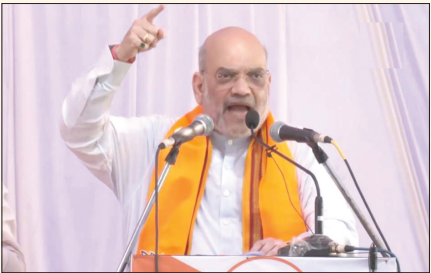


सुरत गुजरात से प्रकाशित, मुंबई, उत्तरप्रदेश, बिहार, राजस्थान, मध्यप्रदेश, उत्तरांचल, उतराखंड, दिल्ली, हरियाणा में प्रकाशित

सुरत-गुजरात, संस्करण शनिवार 06 दिसंबर 2025 वर्ष-8,अंक-279 पृष्ठ-08 मूल्य-01 रूपये

Website : www.krantisamay.com & epaper.krantisamay.com www.facebook.com/krantisamay1 www.twitter.com/krantisamay1

केंद्रीय मंत्री शाह ने अहमदाबाद में स्वदेशोत्सव 2025 का उद्घाटन किया



अहमदाबाद (एजेंसी)। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भारत को आत्मनिर्भर बनाने के सपने को आगे बढ़ाते हुए, केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने अहमदाबाद में स्वदेशोत्सव 2025 का उद्घाटन किया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और उपमुख्यमंत्री हर्ष साधवी भी उपस्थित थे। यह राष्ट्रव्यापी एवसपा 5 से 9 दिसंबर 2025 तक चलेगा। उद्घाटन समारोह के बाद, गृह मंत्री ने स्वदेशी की शक्ति का प्रतीक स्वानुभूति प्रदर्शनी का भी अनावरण किया। इस स्वदेशी उत्सव के दौरान ज्ञान और जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से विभिन्न महत्वपूर्ण विषयों पर विशेष सेमिनार आयोजित किए हैं। तदनुसार, 5 दिसंबर को उद्घाटन दिवस पर पर्यावरण संकल्प सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। 6 दिसंबर को स्टार्टअप उड़ान 2025 और स्वदेशी संकल्प अभियान पर सत्र निर्धारित हैं। 7 दिसंबर के सत्र मातृशक्ति की भूमिका और साइबर सुरक्षा जागरूकता पर केंद्रित होगा। 8 दिसंबर को आयुर्वेद और स्वास्थ्य के साथ-साथ बौद्धिक संपदा अधिकारों पर सेमिनार होगा। अंतिम दिन, 9 दिसंबर को प्राकृतिक खेती और जैविक खेती पर चर्चा होगी। साथ ही, प्रतिदिन शाम 7:00 बजे से रात 10:00 बजे तक विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए जाएंगे।

दिल्ली पुलिस ने नेशनल हेराल्ड मामले की जांच के तहत कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री डी. के. शिवकुमार को नोटिस जारी किया

नई दिल्ली (एजेंसी)। दिल्ली पुलिस ने नेशनल हेराल्ड मामले की जांच के तहत कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री डी. के. शिवकुमार को नोटिस जारी कर वित्तीय और लेनदेन संबंधी विवरण मांगा है। एक अधिकारी ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) द्वारा जारी नोटिस में कहा गया है कि शिवकुमार के पास इस साल तीन अक्टूबर को कांग्रेस नेताओं सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ दर्ज नेशनल हेराल्ड मामले से संबंधित ‘‘महत्वपूर्ण जानकारी होने की संभावना है। नोटिस 29 नवंबर को जारी किया गया था। नोटिस में ईओडब्ल्यू ने शिवकुमार को 19 दिसंबर तक पेश होने या मांगी गई जानकारी उपलब्ध कराने को कहा है। जांच अधिकारियों ने उनकी व्यक्तिगत पुष्टभूमि, कांग्रेस पार्टी के साथ उनके जुड़ाव और उनके या उनकी सहयोगी संस्थाओं द्वारा ‘‘यंग इंडियन को कथित रूप से हस्ततंत्रित धनराशि का पूरा ब्योरा मांगा है। कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री के करीबी सूत्रों ने कहा कि उन्हें भाजपा के साथ के साथ तालमेल नहीं बिटाने के कारण निशाना बनाया जा रहा है और यह दर्शाता है कि वह कांग्रेस के लिए ‘‘झटका झेलने वाले प्रमुख नेताओं में शामिल हैं। उन्होंने कहा कि शिवकुमार कांग्रेस नेताओं में ‘‘सबसे अधिक सहाए गए हैं लेकिन भाजपा उन्हें ‘‘तोड़ने में सफल नहीं होगी।

पुतिन के सम्मान में डिनर में राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे को निमंत्रण नहीं, थरूर को बुलाया, कांग्रेस नाराज

नई दिल्ली (एजेंसी)। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के सम्मान में राष्ट्रपति भवन में शुक्रवार रात डिनर में लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को निमंत्रण नहीं दिया गया है। वहीं कांग्रेस के ही सांसद शशि थरूर को बुलाया गया। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने कहा कि सरकार रोजाना प्रोटोकॉल तोड़ती है और लोकतांत्रिक मूल्यों में विश्वास नहीं रखती। वहीं थरूर के न्योता स्वीकार करने पर रमेश ने कहा, अगर हमारे नेता को बुलाया नहीं गया और हमें बुलाया गया, तो हमें अपनी अंतरात्मा से सवाल करना चाहिए। किसी बुलाया है और किसी नहीं, इसमें राजनीति खेली गई है। इसे स्वीकार करना भी सवाल उठता है। वहीं थरूर ने कहा- मुझे नहीं पता कि निमंत्रण किस आधार पर दिए जाते हैं, लेकिन मैं इस कार्यक्रम में जरूर जाऊंगा। हालांकि, विपक्ष के नेताओं को नहीं बुलाना ठीक बात नहीं है।

ूर्व सीएम उमा भारती ने शादियों में फिजूलखर्ची बंद करने की सलाह देते हुए कहा- नेता अवसर दो नंबर का पैसा खपाने शादियों में करते हैं फिजूलखर्ची

टीकमगढ़ (एजेंसी)। नेता अवसर दो नंबर ा पैसा खपाने के लिए शादियों में फिजूलखर्ची करते हैं। आजकल अधिकांश शादियां मैजिक गार्डन िहो रही हैं और इनमें अत्यधिक खर्च किया जा रहा ा। बड़े-बड़े उद्योगपति शादियों में करोड़ों रुपये ंकर मंच सजाकर डॉसर बुलाते हैं। इतने रुपयों े जारों गरीब बेटियों के विवाह कराए जा सकते हैं। अगर हम सीमित साधनों में काम चलाना शुरू कर ें तो यह भ्रष्टाचार के खिलाफ एक क्रांति होगी। हले अंग्रेजों भारत छोड़ो कहा था, अब भ्रष्टाचारी रात में रहे, लेकिन सुधर जाओ कहना होगा।

यह बात पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने नेकमगढ़ में पत्रकारों से चर्चा के दौरान कही। न्होंने यह भी कहा कि भ्रष्टाचार मिटाने के लिए भगले दस वर्षों तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पद र रहना आवश्यक है। गौरतलब है कि मप्र की पूर्व



मुख्यमंत्री उमा भारती ने अपनी मां के नाम यात्रा निकालने के बाद मीडिया से चर्चा की। जहां पर उन्होंने जनप्रतिनिधियों और उद्योगपतियों की शादियों में होने वाली फिजूलखर्ची को लेकर बयान दिया। उन्होंने नेताओं से बार-बार आग्रह किया कि वे दिखावा न करें, क्योंकि उनकी इज्जत पहले से

ही है।

बच्चे हीन भावना से ग्रस्त हो रहे हैं

चर्चा के दौरान उमा भारती ने कहा कि उन्होंने उद्योगपतियों की शादियों में जाना बंद कर दिया है और अपने गार्ड को ऐसे निमंत्रण पत्र स्वीकार न करने का निर्देश दिया है। उन्होंने कहा कि देश में यह प्रतियस्था आ गई है कि किसके पास ज्यादा सुविधाएं हैं। इससे बच्चे हीन भावना से ग्रस्त हो रहे हैं कि वह कमजोर हैं। यह देखकर माता-पिता प्रतियस्था करते हैं और बच्चों की अच्छी परवरिश के लिए भ्रष्टाचार करना शुरू कर देते हैं, जबकि सीमित साधनों में भी काम चलाया जा सकता है। पूर्व सीएम ने ऐसे में नेताओं से शादियों में फिजूलखर्ची बंद करने की सलाह दी है।

रूस-भारत के रिश्ते नई ऊंचाइयों पर पहुंचेंगे: प्रधानमंत्री मोदी

नई दिल्ली (एजेंसी)। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने शुक्रवार को भारत और रूस के बीच मजबूत और बढ़ते सहयोग की पुष्टि करते हुए इस बात पर जोर दिया कि दोनों देशों के रिश्तों को नई ऊंचाइयों पर ले जाने की जरूरत है।

पीएम मोदी ने शुक्रवार को वार्षिक भारत-रूस शिखर सम्मेलन की शुरुआत में अपने संबोधन में यूक्रेन में चल रहे संघर्ष पर भारत के रुख पर जोर देते हुए कहा 'भारत शांति के साथ है और दुनिया को शांति की ओर लौटना चाहिए।'

पीएम मोदी ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमिर पुतिन का दो दिवसीय भारत के राजकीय दौर के दौरान यहां उनका स्वागत करते हुए दोनों देशों के बीच लंबे समय से जारी और समय की कसौटी पर खरी उत्तरी मित्रता पर जोर दिया। उन्होंने पुतिन को रूसी भाषा में अनुवादित भगवद् गीता की एक कोपी भेंट की, और कहा, 'गीता की शिक्षाएं दुनिया भर में लाखों लोगों को प्रेरित करती हैं।'



पीएम मोदी ने श्री पुतिन के नेतृत्व की तारीफ करते हुए कहा, 'यह दौरा बहुत ऐतिहासिक है,' 'आपने एक अग्रणी नेता की दूरदर्शी सोच की काबिलियत की पूरा किया है।' पीएम मोदी ने शांति के लिए भारत की प्रतिबद्धता को दोहराया, और कहा, 'हम सभी को शांति के रास्ते पर चलना होगा और भारत

हल का समर्थन करते हैं।'

राष्ट्रपति पुतिन ने पीएम मोदी की टिप्पणियों का जवाब देते हुए भारत यात्रा के निमंत्रण के लिए शुक्रिया अदा किया। उन्होंने कहा, 'भारत यात्रा के लिये आमंत्रित जाने के लिए मैं पीएम मोदी का शुक्रगुजार हूं।' राष्ट्रपति पुतिन ने शांति के लिए अपनी प्रतिबद्धता दोहराते हुए कहा, 'शांति के मुद्दे पर, दोनों देश एक साथ हैं।' उन्होंने यह भी भरोसा दिलाया कि रूस विवाद के शांतिपूर्ण हल की दिशा में काम कर रहा है। इस शिखर सम्मेलन का मकसद खासकर रक्षा, ऊर्जा और व्यापार के क्षेत्र में दोनों देशों के रिश्तों को और मजबूत करना है।

उम्मीद है कि इस शिखर सम्मेलन के दौरान दोनों नेता रक्षा सहयोग और आर्थिक भागीदारी बढ़ाने समेत कई मुद्दों पर बात करेंगे। रूस तटस्थ नहीं है और वह शांति के साथ है।' उन्होंने बातचीत और कूटनीतिक प्रयासों के जरिए इस विवाद को खत्म करने की अपील करते हुए कहा, 'हम इस विवाद के शांतिपूर्ण

इंडिगो संकट पर सरकार का एक्शन: 24X7 कंट्रोल रूम, जांच शुरू, 3 दिन में सामान्य होंगी सेवाएं

नई दिल्ली (एजेंसी)। भारत की सबसे बड़ी एयरलाइन, इंडिगो, हाल के वर्षों में अपने सबसे बुरे परिचालन संकटों में से एक से जुड़ा रही है, जिसके कारण बड़े पैमाने पर उड़ानें रद्द हो रही हैं, लंबी देरी हो रही है, हवाई अड्डों पर यात्रियों की भीड़ उमड़ रही है और घरेलू हवाई किरायों में भारी उछाल आ रहा है। पायलटों के लिए संशोधित उड़ान ड्यूटी समय सीमा (एफडीटीएल) नियमों से जुड़ी इन बाधाओं ने प्रमुख मेट्रो मार्गों को प्रभावित किया है, जिससे यात्री फंस गए हैं और एयरलाइनों को समय-सारिणी बनाए रखने में मुश्किल हो रही है।

नागरिक उड्डयन मंत्रालय (MoCA) ने तत्काल कार्रवाई करते हुए एक 24 घंटे का निगरान कक्ष स्थापित किया है, परिचालन संबंधी निदेश जारी किए हैं, अस्थायी नियामक छूट प्रदान की है, और जवाबदेही की जांच तथा सुधारात्मक

लोकसभा में नेशनल सिक्योरिटी सेस बिल पास, वित्त मंत्री बोली पान मसाला-सिगरेट पर लगोगा नया टैक्स

- इसका इस्तेमाल नेशनल सिक्योरिटी में होगा, जिससे कारगिल जैसे हालात में बजट कम ना हो

नई दिल्ली (एजेंसी)। सिगरेट-पान मसाला जैसे प्रोडक्ट पर सरकार अब एक्सट्रा टैक्स लगाएगी। एक्सट्रा टैक्स से आने वाले पैसे को नेशनल सिक्योरिटी के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। यह जानकारी शुक्रवार को लोकसभा में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने दी। लोकसभा में शुक्रवार को हेल्थ सिक्योरिटी से नेशनल सिक्योरिटी सेस बिल पास हो गया। इस बिल के पास होने के बाद पान मसाला जैसी चीजें महंगी हो जाएंगी। बिल पर चर्चा के दौरान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि कारगिल लड़ाई तैयारी की कमी की वजह से हुई। आर्मी जनरलों ने बताया था कि

आरबीआई ने ब्याज दर 25 बेसिस पॉइंट घटाकर 5.25 फीसदी की

नई दिल्ली (एजेंसी)।भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) की मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) ने गवर्नर संजय मल्होत्रा की अध्यक्षता में हुई बैठक में शुक्रवार को रीपो रेट में 25 बेसिस पॉइंट की कटौती करते हुए इसे 5.25 फीसदी कर दिया। यह लगातार तीसरी बार है जब आरबीआई ने एमपीसी बैठक में ब्याज दरों में बदलाव नहीं किया। इस साल पहले ही रेपो रेट में 1 प्रतिशत की कटौती की गई थी, जिससे लोन धारकों को राहत मिली थी। इस बार महंगाई नियंत्रण में होने के बावजूद ब्याज दरों में कोई कटौती नहीं हुई, जिससे लोन लेने वालों की उम्मीदें अधूरी रहीं। गवर्नर ने बताया कि देश इस समय एक गोल्डिलॉक्स पीरियड से गुजर रहा है, जहां महंगाई घट रही है और आर्थिक विकास तेजी से आगे बढ़ रहा है। वर्तमान में महंगाई 2.2 फीसदी के निचले स्तर पर है, जबकि अर्थव्यवस्था 8 फीसदी की मजबूत वृद्धि दर्ज कर रही है। मल्होत्रा ने कहा कि पिछले कुछ महीनों में आर्थिक गतिविधियां तेज हुई हैं और बैंकिंग



सिस्टम और भी सुदृढ़ हुआ है। उन्होंने बताया कि वित्तीय प्रणाली को बेहतर बनाने, कारोबार में आसानी और उपभोक्ता संरक्षण को मजबूत करने के लिए कई नियमों में सुधार किए गए हैं। तरलता की मौजूदगी स्थिति को ध्यान में रखते हुए आरबीआई ने 1 लाख करोड़ रुपये के सरकारी बॉन्ड खरीद (ओएमओ परचेस) की घोषणा की है। इसके साथ ही 5 अरब डॉलर का तीन साल का डॉलर-रुपया स्वीप भी किया जाएगा, जिससे वित्तीय प्रणाली में स्थिरता बढ़ेगी। गवर्नर ने बताया कि हेडलाइन महंगाई में उछेखनीय गिरावट आई है और आगामी महीनों में यह 4 फीसदी के आसपास रहने की उम्मीद है। कोर महंगाई भी स्थिर हो रही है और खाद्य कीमतों के सामान्य स्तर पर आने से दबाव कम हुआ है।



उयायों की सिफारिश के लिए एक उच्च-स्तरीय जाँच शुरू की है। अधिकारियों को उम्मीद है कि उड़ान कार्यक्रम जल्द ही स्थिर होने लगेगे, लेकिन यात्रियों की असुविधाओं का देशव्यापी असर पहले ही पड़ चुका है।

नागर विमानन मंत्री के. राममोहन

नायडू ने शुक्रवार को कहा कि नए उड़ान शुल्क मानदंडों को स्थगित रखने सहित विभिन्न परिचालन उपायों से इंडिगो की उड़ानों में व्यवधान को दूर करने में मदद मिलेगी और अगले तीन दिन में सेवाएं पूरी तरह बहाल होने की उम्मीद है। नायडू ने बयान में कहा कि सरकार ने इंडिगो में

व्यवधान के कारणों का पता लगाने और जवाबदेही तय करने के लिए एक उच्च स्तरीय जांच शुरू करने का भी निर्णय लिया है। उन्होंने कहा कि डीजीसीए के उड़ान ड्यूटी समय सीमा (एफडीटीएल) आदेश तत्काल प्रभाव से स्थगित कर दिए गए हैं। हवाई सुरक्षा से समझौता किए बिना, यह निर्णय पूरी तरह से यात्रियों खासतौर पर वरिष्ठ नागरिकों, छात्रों, मरीजों और अन्य लोगों के हित में लिया गया है जो आवश्यक जरूरतों के लिए समय पर हवाई यात्रा पर निर्भर हैं। मंत्री ने कहा कि सामान्य हवाई सेवाएं यथाशीघ्र बहाल करने के लिए परिचालनात्मक उपाय शुरू कर दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि इन निर्देशों के तत्काल कार्यान्वयन के आधार पर, हम उम्मीद करते हैं कि उड़ान सेवाएं काल तक स्थिर एवं सामान्य हो जाएंगी। हमें उम्मीद है कि अगले तीन दिन में सेवाएं पूरी तरह बहाल हो जाएंगी।

मॉर्डन वॉरफेयर के लिए रिसोर्सेस की जरूरत

वित्त मंत्री निर्माला सीतारमण ने इसपर कहा कि मैं इसकी इम्पॉर्टेंस पर नहीं जाऊँगी लेकिन देश की सुरक्षा को जरूरतों को पूरा करने के लिए हमें रिसोर्सेस की जरूरत है। लाल किले से पीएम ने मिशन सुदर्शन चक्र की जानकारी दी थी। ऑपरेशन सिंदूर के समय तीनों सेनाओं ने शानदार काम किया जिसमें टेक्निकल इंस्ट्रुमेंट्स की जरूरत पड़ी। यही मॉडर्न वॉरफेयर है और इसी के लिए हमें सेस लगाने की जरूरत है। ये पूरा फंड देश के लोगों की सुरक्षा में ही खर्च होगा। हम ये सेस केवल डीमेरिट गुड्स पर ही लगा रहे हैं।

इनकम टैक्स और जीएसटी में छूट को बढ़ाया

वित्त मंत्री ने प्रोडक्ट महंगे करने को लेकर कहा कि हमारी सरकार ने इनकम टैक्स में छूट दी। जीएसटी कार्डिसल का भी धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने हमारी सिफारिशों का माना। हमारी सरकार यह सुनिश्चित करना चाहती है कि ऐसे प्रोडक्ट्स सस्ते न हों। उन्होंने कहा कि एक वित्त मंत्री के रूप में उनका दायित्व धन जुटाना है, यह बात उन्होंने कुछ सत्रियों द्वारा यह पूछे जाने पर कही कि रक्षा बजट के लिए पान मसाले पर कर क्यों लगाया जाए।

भारत में सिगरेट से हर साल 10 लाख लोगों की मौत

विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक, पूरी दुनिया में हर साल सिगरेट पीने की वजह से 80 लाख से ज्यादा लोगों की प्रीमैच्योर डेथ होती है। वहीं भारत में हर साल स्मोकिंग के कारण 10 लाख से अधिक लोगों की मौत हो जाती है।



दिसंबर से लागू होंगे। ट्रम्प प्रशासन ने सभी दूतावासों को निर्देश जारी किए हैं। अगस्त 15

स्टडी वीजा एफ-1, एम-1 और जे-1 साथ ही बिजिटर वीजा बी-1, बी-2 के लिए

संचार साथी ऐप: अपेक्षा है निजता बनाम सुरक्षा के बीच संतुलन की



ललित गर्ग

वास्तविकता यह है कि डिजिटल युग आज अवसरों के साथ-साथ अभूतपूर्व संकटों का भी युग है। साइबर अपराध, चोरी, जासूसी, डेटा हेरफेर, गलत सूचना, आतंकवादी नेटवर्किंग-इन सबने सुरक्षा की चुनौतियों का नया स्वरूप निर्मित किया है। संयुक्त राष्ट्र तक यह स्वीकार कर चुका है कि अगला विश्वयुद्ध यदि हुआ, तो वह साइबर मोर्चे पर भी लड़ा जाएगा। ऐसे समय में क्या किसी राष्ट्र की सरकार को निष्क्रिय खड़ा रहना चाहिए? निश्चित रूप से नहीं।

भारत की लोकतांत्रिक राजनीति में एक विचित्र प्रवृत्ति विकसित होती दिख रही है, जहाँ सत्ता द्वारा उठाए गए प्रत्येक कदम को विपक्ष संदेह की दृष्टि से देखता है। संचार साथी ऐप को लेकर इन दिनों इसी प्रकार का विवाद एवं विरोध का वातावरण बना हुआ है। केंद्र सरकार की यह सोच कि हर नए स्मार्टफोन में इस ऐप को अनिवार्य किया जाए, विपक्ष ने इसे निजता एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता का उल्लंघन बताते हुए कठोर शब्दों में चुनौती दी और संसद के शीतकालीन सत्र में इसे बड़ा मुद्दा बना दिया है और इससे व्यक्ति के जीवन में सरकारी हस्तक्षेप बढ़ने की आशंकाएं व्यक्त की है। विपक्ष ने इसे संवैधानिक अधिकारों का अतिक्रमण व नागरिकों की निगरानी करने वाला टूल बताया। इस बहस के बीच विपक्ष को नया मुद्दा मिलते देख केंद्र सरकार ने अनिवार्य तौर पर ऐप प्री-इंस्टॉल करने का अपना फैसला वापस ले लिया। सरकार ने स्थिति की संवेदनशीलता को देखते हुए फिलहाल इसे स्वेच्छिक बना दिया है अर्थात जो चाहे ऐप को रखे, जो चाहे उसे हटाए।

परंतु इस विवाद ने एक महत्वपूर्ण प्रश्न उठा दिया है कि क्या हम केवल विरोध की राजनीति में वास्तविक चुनौतियों और आवश्यकताओं को भुला रहे हैं? वास्तविकता यह है कि डिजिटल युग आज अवसरों के साथ-साथ अभूतपूर्व संकटों का भी युग है। साइबर अपराध, चोरी, जासूसी, डेटा हेरफेर, गलत सूचना, आतंकवादी नेटवर्किंग-इन सबने सुरक्षा की चुनौतियों का नया स्वरूप निर्मित किया है। संयुक्त राष्ट्र तक यह स्वीकार कर चुका है कि अगला विश्वयुद्ध यदि हुआ, तो वह साइबर मोर्चे पर भी लड़ा जाएगा। ऐसे समय में क्या किसी राष्ट्र की सरकार को निष्क्रिय खड़ा रहना चाहिए? निश्चित रूप से नहीं। इसलिए संचार साथी ऐप मात्र निगरानी का यंत्र नहीं है, बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा, नागरिक संरक्षण एवं डिजिटल अपराध नियंत्रण की रणनीतिक आवश्यकता के रूप में उभरा है। सरकार का सही कहना था कि डिजिटल होती दुनिया में लगातार बढ़ते साइबर अपराधों से नागरिकों को सुरक्षा देने के मकसद से यह पहल की गई थी। उसका कहना था कि लगातार जटिल होते साइबर अपराधों पर अंकुश लगाने के लिये ऐसी पहल अपरिहार्य है।

विपक्ष का विरोध इसलिए भी एकांगी है क्योंकि केवल यह निजता के सवाल पर केंद्रित है। परंतु निजता का अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 में निहित, पूर्ण स्वतंत्र नहीं, बल्कि परिस्थितिनिष्ठ है। लोकतंत्र व्यक्ति को अधिकार देता है, साथ ही साझा सुरक्षा की जिम्मेदारी भी मांगता है। जब डिजिटल मोर्चे पर राष्ट्रीय अखंडता, आर्थिक व्यवस्था, सामरिक रहस्य और सामाजिक शांति पर संकट मंडराते हों,



तो सरकार को हस्तक्षेप करना नैतिक रूप से उचित ही नहीं, बल्कि आवश्यक हो जाता है। अमेरिका, चीन, जर्मनी, ब्रिटेन-सभी देशों के पास निगरानी आधारित साइबर सुरक्षा प्रणालियाँ हैं। क्या उनकी लोकतांत्रिक संरचनाएँ इस कारण क्षीण हो गई? नहीं, क्योंकि निगरानी और सुरक्षा के बीच संतुलन स्थापित किया गया। भारत को भी इसी संतुलन की आवश्यकता है। यह सही है कि किसी भी डिजिटल ऐप में निगरानी का वहनीय स्वरूप रखना चाहिए, जिससे नागरिक की व्यक्तिगत जिंदगी पर अनावश्यक हस्तक्षेप न हो। सरकार ने भी यही स्पष्ट किया है कि संचार साथी नागरिक के निजी जीवन में दखल नहीं देना चाहता, बल्कि उसे साइबर अपराध, हैकिंग, धोखाधड़ी, फर्जीबाँडा, एवं डिजिटल आतंकवाद से बचाने हेतु काम करेगा। विडंबना यह है कि विपक्ष इस ऐप को 'निष्ठा परीक्षण', 'मनोवैज्ञानिक निगरानी' और 'गोपनीयता हनन' का उपकरण बताकर भय पैदा कर रहा है, जबकि पूर्व में स्वयं उनकी सरकारें समान तंत्र विकसित कर चुकी हैं, चाहे वह आधार डेटा सुरक्षा हो, सोशल मीडिया मॉनिटरिंग सेल हो या राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसियों के निगरानी प्रोटोकॉल।

सवाल यह है कि यदि अपराधी, आतंकवादी, अलगाववादी, साइबर गैंग्स संगठित डिजिटल हथियारों का उपयोग कर रहे हैं, तो क्या सामान्य नागरिकों को असुरक्षित छोड़ दिया जाए? क्या यह लोकतंत्र का तकाजा है कि सरकार देखती रहे और समाज अपराध की प्रयोगशाला बन जाए? वास्तव में यह संकट केवल भारत का नहीं, विश्व का है। आज की दुनिया में जो राष्ट्र डिजिटल नियंत्रण तंत्र विकसित नहीं करता,

उसकी सुरक्षा दीवारें कागज की नाव जैसी सिद्ध होती हैं। इसलिए यह कहना कि संचार साथी ऐप अनावश्यक या दमनकारी है, वस्तुस्थिति से आंखें मूंद लेने जैसा है। निश्चित रूप से एक सवाल उठता है, क्या ऐप डेटा सुरक्षा की गारंटी देगा? यह बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न है। सरकार को इस ऐप के उद्देश्य और डाटा संचालन नीति को पारदर्शी रूप में सार्वजनिक करना चाहिए। यदि इस पर स्वतंत्र ऑडिट हो, निजता सुरक्षा प्रावधान हों, दुरुपयोग को रोकने वाली न्यायिक निगरानी हो तो विरोध स्वतः समाप्त हो जाएगा। परंतु विपक्ष का विरोध नीतिगत सुधारों की दिशा में न होकर केवल राजनीतिक अवसरवाद प्रतीत होता है। यह भी सही है कि नागरिकों की चिंताएँ निरधार नहीं, भारत में डेटा सुरक्षा कानून अभी भी परिपक्व नहीं है, डिजिटल संरचनाएँ जवाबदेही की दृष्टि से मजबूत नहीं हैं। अतः संचार साथी के विकास के साथ-साथ देश में निजता सुरक्षा कानूनों को और अधिक कठोर, डंडात्मक एवं न्यायिक रूप से संरक्षित बनाने की आवश्यकता है।

यदि इस ऐप के कार्यों पर दृष्टि डालें तो उसके पीछे सोच यह है कि मोबाइल संचार के माध्यम से होने वाले अपराधों की पहचान, रिवॉर्पिंग और ट्रैकिंग को व्यवस्थित किया जा सके। यह व्यक्ति की निगरानी का उपकरण कम और अपराध नियंत्रण की प्रणाली अधिक है। भारत में साइबर अपराधों में प्रति वर्ष 63 प्रतिशत वृद्धि दर्ज की जा रही है, लाखों लोग ऑनलाइन धोखाधड़ी के शिकार बन रहे हैं, बैंकिंग ठगी से लेकर सोशल मीडिया मनोवैज्ञानिक अपराधों तक का दायरा बढ़ रहा है। क्या सरकार की चुप्पी इन अपराधियों को खुला

मैदान नहीं दे देती? इसलिए संचार साथी जैसे कदमों का उद्देश्य नागरिक सुरक्षा का विस्तार है, न कि लोकतांत्रिक स्वतंत्रता का संकुचन।

कठोर सत्य यह है कि राष्ट्र के केवल अधिकारों पर आधारित नहीं होते, जिम्मेदारियों और सुरक्षा तंत्रों पर भी टिके होते हैं। एक नागरिक के रूप में हम यह अपेक्षा करते हैं कि हमारा डेटा सुरक्षित हो, हमारा पैसा सुरक्षित हो, हमारा देश सुरक्षित हो परंतु जब सुरक्षा के लिए कदम उठाया जाए, तो हम विरोध में खड़े हो जाते हैं। यह राजनीतिक अधिक है, जहाँ हम एक विश्वव्यापी सिद्धांत को भूल जाते हैं कि 'स्वतंत्रता जिम्मेदारी के साथ ही टिक सकती है।' इसलिए संचार साथी ऐप पर संतुलित दृष्टि ही सार्थक है। सरकार को उसकी संरचना पारदर्शी, उत्तरदायी और कानून नियंत्रित रखनी चाहिए, और विपक्ष को इस तथ्य को स्वीकार करना चाहिए कि डिजिटल भारत की सुरक्षा चुनौतियाँ केवल नारे से हल नहीं होंगी, बल्कि तकनीकी सुरक्षा तंत्रों से ही नियंत्रण संभव होगा। लोकतंत्र में आलोचना आवश्यक है, परंतु रचनात्मक आलोचना, जिसमें सुधार की मांग होती है, न कि केवल अस्वीकरण। यदि राजनीतिक वर्ग इस बहस को इसी दिशा में ले जाए, तो संचार साथी ऐप न केवल विवादित विषय रहेगा बल्कि डिजिटल सुरक्षा के लिए नागरिक-हितकारी उपकरण के रूप में स्थापित भी होगा।

निस्संदेह, आज के डिजिटल युग में व्यक्ति का डेटा बेहद महत्वपूर्ण है। जिसकी हर कीमत पर सुरक्षा की जानी चाहिए। वहीं इसके साथ ही इस बात की भी पड़ताल होनी चाहिए कि कहीं कुछ अन्य ऐप हमारे डेटा में तो संध नहीं लगा रहे हैं? सरकार को इससे उपभोक्ता की सुरक्षा करनी होगी। वहीं तर्क दिया जा रहा है कि संचार साथी ऐप को अनिवार्य करने के बजाय आम लोगों को नई तकनीक और इसके इस्तेमाल के लिये सतर्क करने को देशव्यापी जागरूकता अभियान चलाया जाना चाहिए। साथ ही इसके लिये आम जनता को प्रशिक्षण भी दिया जाना चाहिए। जिससे तकनीक के जरिये साइबर अपराधियों पर अंकुश लगाने की मुहिम को गति दी जा सके। अतः यह समझना होगा कि राष्ट्रीय सुरक्षा और निजता-दोनों अनिवार्य हैं। चुनौती इन्हें संतुलित करने की है, न कि किसी एक को दूसरे के विरुद्ध खड़ा करने की। यदि यह संतुलन नीति, पारदर्शिता और जवाबदेही के साथ बने, तो संचार साथी ऐप देश के डिजिटल भविष्य की सुरक्षा का सेतु बन सकता है। विरोध की राजनीति नहीं, समझ और सामाजिक राजनीति आज की आवश्यकता है, यही इस ऐप की वास्तविकता और उपयोगिता को समझने की दिशा है।

संपादकीय

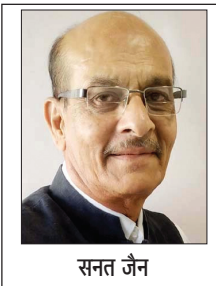
हिंद-रूस दोस्ती जिंदाबाद

भारत और रूस की दोस्ती सात दशक पुरानी है। दो दोस्तों ने, इतने लंबे वक्त तक, कई तुफानों और इम्तिहानों के बावजूद, दोस्ती को बरकरार रखा है, यकीनन यह एक मिसाल है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भारत के प्रवास पर हैं। वह अपने साथ दोस्ती की नई पेशकशें और आयाम लेकर आए हैं। प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति पुतिन के 5 दिसंबर को शिखर, द्विपक्षीय संवाद के बाद जो साझा बयान जारी किया जाएगा और जिन समझौतों पर हस्ताक्षर किए जाएंगे, उनके बाद दोस्ती, सहयोग, समर्थन नई ऊंचाइयों छुएंगे। राष्ट्रपति पुतिन ने भी रूस से यात्रा आरंभ करने से पूर्व इसी आशय का बयान दिया था। दरअसल रूस भारत को ऐसे 'रणनीतिक साझेदार' के रूप में स्वीकार करना चाहता है, जिसकी साझेदारी असीम, निस्सीम अर्थात् सीमारहित हो। कोई सीमा नहीं, रूस और चीन की साझेदारी ऐसी है। रूस भारत को भी उन्हीं समीकरणों में देखना चाहता है। राष्ट्रपति पुतिन ने अपनी इच्छा फिर दोहराई है कि रूस, भारत, चीन को एक 'तिकड़ी' बन जाना चाहिए। वह 'तिकड़ी' अमरीका से मुकाबला करने में सक्षम और सशक्त साबित होगी। बेशक पुतिन की यह इच्छा विचारणीय है, क्योंकि रूस पर अकेले अस्तित्व यथावत है। उसकी अर्थव्यवस्था को ज्यादा धक्के नहीं लगे हैं। भारत और चीन ने रूस से कच्चा तेल खरीद कर उसकी आर्थिक मदद की है। हालांकि भारत ने अब यह खरीद एक-तिहाई कर दी है। कारण अमरीका का दबाव ही नहीं है। रूस यूक्रेन और परोक्ष रूप से अमरीका, यूरोप, नाटो देशों के खिलाफ लगातार युद्ध लड़ रहा है। रूस से कच्चा तेल लेने के कारण ही अमरीका ने भारत पर, जुगानों के रूप में, 25 फौसदी अतिरिक्त टैरिफ थोपा था। भारत पर कुल टैरिफ 50 फौसदी है। अमरीका चीन को भी टैरिफ की धमकियां देता रहा है। बहरहाल रूस भारत को 'असीमित' रणनीतिक साझेदार के रूप में देखना चाहता है। रूसी संसद ने 'पेलोस' समझौते को भी मंजूरी दी है। उसके तहत भारत रूस के एयरबेस, नौसेना पोर्ट, युद्धपोत, सैन्य बल एवं साजो सामान, फ्यूल, संसाधन आदि इस्तेमाल कर सकेगा। रूस के 5 युद्धपोत, 10 सैन्य विमान, 3000 सैनिक आगामी 5 साल के लिए भारतीय जमीन पर तैनात किए जा सकेगें। भारत की इतनी ही सैन्य ताकत रूसी जमीन पर तैनात होगी। यह समझौता 'रिसिप्रोकल एक्सचेंज ऑफ लॉजिस्टिक सपोर्ट' (आइएलओएस) है, जो रूसी संसद में पारित किया गया है। इससे भारत और रूस दो देश तो रहेंगे, लेकिन उनकी सैन्य-शक्ति 'एकाकार' हो जाएगी, जिसे सोच कर ही दुश्मन कांपने लगेगा। बेशक दुश्मन की शक्ति कमजोर पड़ेगी। यही नहीं, भारत-रूस के बीच 'नागरिक परमाणु करार' भी होगा।

चिंतन-मनन

मन को जगाएं

दूसरा महायुद्ध चल रहा था। भीषण बमबर्षों हो रही थी। पूरा लंदन नगर संत्रस्त था। सारे नगर में भय का साम्राज्य छाया हुआ था। पर उसी नगर में एक बूढ़ी महिला निश्चित रूप से सोती और निश्चित जागती। आस-पास के लोगों की नींद पूरी तरह गायब हो चुकी थी। वे न सुख से सो पाते और न सुख से जाग पाते। दूसरे सभी जागते, किन्तु बुढ़िया निश्चित सोती, गहरी नींद लेती। लोगों ने बुढ़िया से पूछा, मां! क्या बात है? सारा नगर भय से आप्रान्त है। यहां कोई भी सुख की नींद नहीं सो सकता। तुम कैसे सुखपूर्वक सो जाती हो? इसका रहस्य क्या है? बुढ़िया ने कहा, बेटी! इसका रहस्य यही है कि मेरा प्रभु सदा जागता है। फिर मैं क्यों जागती रहूँ? दो को जागने की जरूरत नहीं है। यह सच है। जब मन जाग जाता है, फिर कोई जागे या न जागे, कोई जरूरत नहीं है। किसी को जागाने की भी जरूरत नहीं है। वास्तविकता तो यह है कि मन के जागने पर कोई सोया रह नहीं सकता। सबको जागना ही पड़ता है। एक के जागने पर सब जाग जाते हैं। एक के सोने पर सब सो जाते हैं। मन का मार्ग बहुत लम्बा-चौड़ा और दीर्घ है। वह एक क्षण में सारी दुनिया का चक्कर लगा सकता है। मन को साधने के बाद उसका भटकाव मिट जाता है, प्रमाद मिट जाता है, सोने की आदत मिट जाती है। फिर वह पूर्ण अनुशासित हो जाता है, नियंत्रित हो जाता है। जागरूकता का विकास सिद्धान्त को जानने मात्र से नहीं होता। उसका विकास तब होता है, जब साधक उचित दिशा में जागरूकता का अभ्यास करे।



सनत जैन

भारत-रूस के दोस्ताना ताल्लुक सात दशक से बराबर चले आ रहे हैं। फिर चाहे राजनीतिक, आर्थिक या सांस्कृतिक संबंधों की बात ही क्यों न हो। हिन्दी सिने जगत ने तो दोनों देशों के सांस्कृतिक संबंधों को प्रगाढ़ बनाने में अहम भूमिका अदा की। वैश्विक धरातल पर फिक्मयी जगत की बात करें तो राज कपूर का नाम जरूर आता है, जिन्होंने 70 एमएम के रुपहले पर्दे पर मेरा नाम जोकर फिल्म को प्रदर्शित कर भारत-रूस संबंधों को एक तरह से मजबूत करने में सहयोग प्रदान किया। भारत-रूस संबंध आज उस ऐतिहासिक विरासत के साथ खड़े हैं, जिसकी जड़ें बीते कई दशकों में गहराई तक जा पहुंची हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हैदराबाद हाउस में राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ मुलाक़ात के दौरान जब इस दोस्ती की ध्रुव तारे जैसा अटल बताया, तो यह सिर्फ कूटनीतिक विनम्रता नहीं थी; बल्कि उन यादों, संघर्षों और वैश्विक उथल-



दिलीप कुमार पाठक

विदेश जाकर अर्थशास्त्र डॉक्टरेट की डिग्री हासिल करने वाले डॉ. अम्बेडकर पहले भारतीय थे, जब वे 1926 में भारत आए तब उन्हें मुंबई की विधानसभा का सदस्य चुना गया ' अम्बेडकर आजाद देश के पहले कानून मंत्री थे, साल 1990 में उन्हें भारत के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया था ' डॉ. भीमराव अंबेडकर भारत के संविधान निमाता भी थे, इसलिए आजाद भारत की लोकतांत्रिक राजनीतिक में उनका कद बहुत विशाल है, आज 06 दिसम्बर को डॉ. अम्बेडकर का परिनिर्वाण दिवस मनाया जाता है, 'पूण्यतिथि को ही परिनिर्वाण दिवस कहते हैं ' डॉ. अम्बेडकर संविधान निमाता के साथ परम विद्वान, सामाजिक न्याय, एवं स्त्रियों के अधिकारों के लिए भी याद किए जाते हैं ' आज हमारे देश में स्त्रियों की स्थिति में सुधार हो रहा है, इसका सबसे बड़ा श्रेय भी बाबा साहेब अम्बेडकर को जाता है, डॉ. अम्बेडकर का कद भारतीय राजनीति में वही है जो नेहरू, पटेल, का है, देश दुनिया में उनके चाहने वाले बाबा साहेब कहकर संबोधित करते हैं ' आज के दौर में लोगों की धारणा है कि डॉ. अम्बेडकर दलितों के नेता थे, लेकिन वे देश के अग्रणी नेता थे जो खुद एक विचार बन गए ' किसी भी व्यक्ति का परिनिर्वाण दिवस मनाया जाना इसलिए महत्वपूर्ण कि इस दिन लोग उनकी बुराईयों की बजाय उनकी अच्छाईयों को याद करते हैं और उसे अपने जीवन में उतारने का संकल्प भी लेते हैं । बाबा साहेब डॉ.



भीमराव रामजी अम्बेडकर बिना भेदभाव के दलितों, पिछड़ों, महिलाओं और देश के सर्वांगीण विकास के लिए आजीवन समर्पित रहे । बाबा साहेब डॉ. की मृत्यु 6 दिसम्बर 1956 को हुई थी, यही कारण है कि डॉ. अम्बेडकर महापरिनिर्वाण दिन या पुण्यतिथि हर साल उन्हें 6 दिसम्बर को देश में ही नहीं विदेशों में भी श्रद्धांजलि और सम्मान देने के लिये मनाया जाता है । वे, 'भारतीय संविधान के जनक' हैं, उनके प्रयास और मेहनत के परिणाम के बाद ही भारत को अपना संविधान प्राप्त हो पाया है, डॉ. अम्बेडकर बचपन से ही शिक्षा प्राप्त करने के लिए बहुत ही उत्साहित रहते थे, परन्तु महार जाति के होने के कारण उनके साथ भेद-भाव किया जाता था । उनकी मृत्यु विवादित रही कि उनकी मृत्यु स्वाभाविक थी या हत्या, जिसका आज तक पता न चल सका । इस दिन दलित वर्ग उनकी प्रतिमा पर फूल, माला, दीपक और मोमबत्ती जलाकर और संविधान की प्रति भेंट करके उन्हें श्रद्धांजलि देते हैं और एक सबसे प्रसिद्ध नारा 'बाबा साहेब अमर रहे' लगाते हैं । इस अवसर पर बौद्ध भिक्षु सहित कुछ लोग कई पवित्र गीत भी गाते हैं ' डॉ. अंबेडकर ने अपने

क्रांति की ओर बढ़ रही है, तो भारत और रूस का सहयोग एक बार फिर निर्णायक साबित हो गया है। क्रिटिकल मिनरल्स में संयुक्त पहलों से सुरक्षित सप्लाय चैन बनेगी, वहीं शिपबिलडिंग सहयोग ह्यूमेक इन इंडियाहू को नई गति देगा। यह सहयोग सिर्फ औद्योगिक लाभ तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि रोजगार, कौशल और क्षेत्रीय संपर्कता को लेकर भी गहरे प्रभाव डालेगा। इतिहास गवाह है कि भारत-रूस की दोस्ती संकटों और संघर्षों की भट्टी में तपकर बनी है। यही वजह है कि प्रधानमंत्री मोदी पहलगाम पर हुए आतंकवादी हमले से लेकर रूस के क्रोक्स सिटी हॉल हमले तक का जिक्र करते हुए कहते हैं, कि आतंकवाद की जड़ें भले भिन्न भूभागों में हों, पर उद्देश्य एक ही होता है, मानवता पर हमला। यही कारण है कि भारत और रूस ने अंतरराष्ट्रीय मंचों, यूनू, जी-20, ब्रिक्स, एससीओ सभों पर आतंकवाद के खिलाफ एकजुट होकर आवाज उठाई है। दोनों देशों की यह नैतिक एकता वैश्विक राजनीति में एक संतुलनकारी भूमिका निभाती है। अंतराष्ट्रीय स्तर पर बहुते आतंकवादी हमले और शांतिप्रिय देशों की बढ़ती परेशानी के बीच जब आज प्रधानमंत्री मोदी यह कहते हैं, कि भारत न्यूट्रल नहीं है, भारत शांति के पक्ष में है, तो यह वक्तव्य वैश्विक कूटनीति के एक नए दृष्टिकोण की ओर संकेत करता है। युट्रिनेरपेक्षता के धरातल पर चलते हुए भारत शांति को अपनी विदेश नीति का केंद्र मानता है और रूस के साथ मिश्रकर इस दिशा में काम करता रहा है। पुतिन



द्वारा राजघाट पहुंचकर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को श्रद्धासुमन अर्पित करना इसी संदेश को आगे बढ़ाता है कि शांति और शांति की अवधारणाएँ एक-दूसरे के विरोधी नहीं, बल्कि पूरक हो सकती हैं। इस अवसर पर यह स्वीकारना आवश्यक है, कि रूस-भारत संबंध पुतिन के नेतृत्व में नई ऊंचाइयों तक पहुंचे हैं। मोदी का यह कहना, कि हर परिस्थिति में पुतिन की दूरदर्शिता ने इस रिश्ते को मजबूती दी। केवल राजनयिक प्रशंसा नहीं, बल्कि संबंधों की निरंतरता के प्रति आभार है। दुनिया बहुध्रुवीय युग की ओर बढ़ रही है। ऐसे समय में भारत-रूस की यह स्थिर साझेदारी ध्रुव तारे की तरह ही मार्गदर्शक है, अटल, स्थिर और विश्व व्यवस्था में संतुलन का प्रतीक। आने वाले वर्षों में यह संबंध केवल रणनीतिक नहीं, बल्कि वैश्विक शांति और स्थिरता की दिशा में निर्णायक भूमिका निभाएंगे ऐसी उम्मीद है।

अम्बेडकर के सामाजिक न्याय की त्रिवेणी: एकता, बंधुत्व और सम्मान

में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व को पहचानता है । उनका यह दृढ़ विश्वास था कि जब तक आर्थिक और सामाजिक विषमता समाप्त नहीं होगी, तब तक जनतंत्र की स्थापना अपने वास्तविक स्वरूप को ग्रहण नहीं कर सकेगी ' दरअसल सामाजिक चेतना के अभाव में जनतंत्र आत्मविहीन हो जाता है । ऐसे में जब तक सामाजिक जनतंत्र स्थापित नहीं होता है, तब तक सामाजिक चेतना का विकास भी संभव नहीं हो पाता है ।

डॉ. अम्बेडकर भारतीय समाज में स्त्रियों की हीन दशा को लेकर काफी चिंतित थे । उनका मानना था कि स्त्रियों के सम्मानपूर्वक तथा स्वतंत्र जीवन के लिए शिक्षा बहुत महत्वपूर्ण है । अम्बेडकर ने हमेशा स्त्री-पुरुष समानता का व्यापक समर्थन किया । इस संबंध में उनका कहना था 'पति-पत्नी के बीच का रिश्ता करीबी दोस्तों के जैसा होना चाहिए' और 'मैं एक समुदाय की प्रतिनि को उस डिग्री से मांपता हूँ जो महिलाओं ने हासिल की है ।' यही कारण है कि उन्होंने स्वतंत्र भारत के प्रथम विधिमंत्री रहते हुए 'हिंदू कोड बिल' संसद में प्रस्तुत किया और अहिन्दू स्त्रियों के लिए न्याय सम्मत व्यवस्था बनाने के लिए इस विधेयक में उन्होंने व्यापक प्रावधान रखे । उल्लेखनीय है कि संसद में अपने हिन्दू कोड बिल मसौदे को रोके जाने पर उन्होंने मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया । इस मसौदे में उत्तराधिकार, विवाह और अर्थव्यवस्था के कानूनों में लैंगिक समानता की बात कही गई थी । दरअसल स्वतंत्रता के इतने वर्ष बीत जाने के पश्चात व्यावहारिक धरातल पर इन अधिकारों को लागू नहीं किया जा सका है, वहीं आज भी महिलाएँ उत्पीड़न, लैंगिक भेदभाव हिंसा, समान कार्य के लिए असमान वेतन, दहेज उत्पीड़न और संपत्ति के अधिकारों का मिलने जैसी समस्याओं से जूझ रही हैं । डॉ. अम्बेडकर ने अपनी विचारधारा, अपनी सोच एवं शिक्षा से सभी की जिन्दगी में सकारात्मकता फैलाई ' डॉ अम्बेडकर के विचार हमारे देश के लिए महान विरासत हैं, जो हमेशा प्रासंगिक रहेंगे '

जीवन के 65 सालों में सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, शैक्षणिक, धार्मिक, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, साहित्यिक, औद्योगिक, संवैधानिक आदि क्षेत्रों में अनगिनत कार्य करके राष्ट्र निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान दिया और आधुनिक भारत की नींव रखी थी, ऐसा एक सच्चा और समर्पित देशभक्त ही कर सकता है, उन्होंने कहा था 'हम भारतीय हैं, सबसे पहले भी और अंत में भी ' लेकिन देश उनके इस योगदान को लेकर आज भी जागरूक नहीं है ।

उनके विचार व सिद्धांत भारतीय राजनीति के लिए हमेशा से प्रासंगिक रहे हैं । दरअसल वे एक ऐसी राजनीतिक व्यवस्था के हिमायती थे, जिसमें राज्य सभी को समान राजनीतिक अवसर दे तथा धर्म, जाति, रंग तथा लिंग आदि के आधार पर भेदभाव न किया जाए। उनका यह राजनीतिक दर्शन व्यक्ति और समाज के परस्पर संबंधों पर बल देता है । उनका कहना था 'राजनीतिक लोकतंत्र तब तक नहीं चल सकता जब तक कि सामाजिक लोकतंत्र का आधार नहीं होता । सामाजिक लोकतंत्र का क्या अर्थ है? इसका मतलब जीवन का एक तरीका है जो जीवन के सिद्धांतों के रूप

क्षेत्र के हिसाब से ऐप्स व
हुँह सके और डाउनलोड क
पाएँ।

मोटोरोला मोबाइल
इंडिया के मैनेजिंग डायरेक्टर
टी. एन. नरसिम्हन ने भी
अपना उत्साह व्यक्त करते हु
कहा, मोटोरोला में, हम
हमेशा भारत में अपने यूज
को एक उत्कृष्ट और उन
क्षेत्र के हिसाब से अनुभव द
को प्राथमिकता दी है और
इंडस ऐपस्टोर हमारे इ
दुष्टिकोण पर पूरी तरह से ख
उतरता है। इस स्वदेश
प्लेटफॉर्म को एकीकृत करके
हम यूजर्स को एक नया माध्यम प्रदान कर रहे हैं ज
उनको अपनी संस्कृति के हिसाब से ऐप खोजने व
विकल्प देकर उनके अनुभव को बेहतर बनाता है। इ
साझेदारी से भारतीय डेवलपर्स को भी लाभ होगा। इ
सहयोग से एक और बड़ा लाभ यह है कि इंडस ऐपस्ट
का विशिष्ट वितरण मॉडल, भारतीय डेवलपर्स को उन
सही यूजर्स को जोड़ेगा।

संक्षिप्त समाचार

चिली: कक्षा के दौरान स्मार्टफोन के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने वाला नवीनतम देश बना

सैंटियागो, एजेंसी। चिली ने प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालयों में कक्षाओं के दौरान मोबाइल फोन और अन्य स्मार्ट उपकरणों के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने वाला विधेयक पारित किया है। नया कानून अगले साल से लागू होगा, जिससे चिली युवा छात्रों के बीच स्मार्टफोन के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाने वाला नवीनतम देश बन जाएगा ताकि इसके हानिकारक प्रभावों को कम किया जा सके और कक्षा में ध्यान भटकने से बचा जा सके। स्कूलों में स्मार्टफोन के इस्तेमाल पर विभिन्न स्तरों के प्रतिबंध लगाने वाले अन्य देशों में फ्रांस, ब्राजील, हंगरी, नीदरलैंड और चीन शामिल हैं। शिक्षा मंत्री निकोलस केटाल्डी ने निर्णय के बाद सोशल मीडिया पर लिखा, ‘हम बच्चों और किशोरों के लिए एक सांस्कृतिक परिवर्तन को आगे बढ़ा रहे हैं, जिन्हें आज पहले से कहीं अधिक एक-दूसरे के चेहरे देखने, अवकाश के दौरान सामाजिक मेलजोल बढ़ाने और सीखने को और अधिक बढ़ावा देने के लिए एकाग्रता हासिल करने की आवश्यकता है।’

रूस के जेल में बंद एक अमेरिकी नागरिक ने की गार्डों की पिटाई, सजा बढ़ाई

मास्को, एजेंसी। रूस में पुलिस अधिकारी की पिटाई के दोषी पाए गए एक अमेरिकी की सजा बुधवार को बढ़ा दी गई, जब उसे जेल प्रहरियों पर हमला करने का दोषी पाया गया। रॉबर्ट गिलमैन, जिन्हें रूसी मीडिया में पूर्व अमेरिकी मरीन के रूप में पहचाना गया था, को शुरू में 2022 में 3-1/2 साल की सजा सुनाई गई थी, जब उन्हें एक पुलिस अधिकारी के साथ मारपीट करने का दोषी ठहराया गया था, जिसे ट्रेन से उतारकर गड़बड़ी पैदा करने के लिए दोषी ठहराया गया था। बाद में उन्हें एक सेल जांच के दौरान जेल निरीक्षक पर हमला करने, एक अन्वेषक की पिटाई करने और एक गार्ड पर हमला करने का दोषी ठहराया गया, और अक्टूबर 2024 में उन्हें आठ साल और एक महीने की सजा सुनाई गई। बुधवार को, दक्षिण-पश्चिमी रूस के वोरोनिश क्षेत्र की एक अदालत ने, जहां गिलमैन अपनी सजा काट रहा है, उसकी सजा को 10 वर्ष तक बढ़ा दिया, क्योंकि उसे दो जेल प्रहरियों की पिटाई का दोषी पाया गया था।

ईरू की सब्सिडी में देरी को लेकर बढ़ते विवाद में ग्रीक किसानों ने सीमा पार करने के रास्ते बंद किए

एथेंस, एजेंसी। उत्तरी ग्रीस के किसानों ने भूधधार धोटेाले की जांच से जुड़े यूरोपीय संघ समर्थित सब्सिडी भुगतान में देरी के विरोध में बुधवार को सीमा चौकियों पर यातायात बाधित कर दिया। ट्रैक्टरों के काफिलों ने उत्तरी मैसेडोनिया, बुल्गारिया और तुर्की के मार्गों को अवरुद्ध कर दिया, जिससे चालकों को लंबा चक्कर लगाना पड़ा। सप्ताहांत में सैकड़ों किसान सड़कों पर उतर आए और कई इलाकों में ट्रैक्टरों से सड़कें जाम कर दीं। ग्रीस में किसानों द्वारा विरोध प्रदर्शन आम बात है, लेकिन नवीनतम अशांति यूरोपीय संघ के धन के लिए व्यापक धोखाधड़ी के दावों के खुलासे के बाद सब्सिडी भुगतान में देरी को लेकर भड़की। इस घोटाले के कारण जून में पांच वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों को इस्तीफा देना पड़ा और कृषि सब्सिडी से संबंधित कार्य करने वाली राज्य एजेंसी को चरणबद्ध तरीके से बंद करना पड़ा। यूरोपीय लोक अभियोजक कार्यालय द्वारा की गई एक जांच के जवाब में हाल के हफ्तों में ग्रीस भर में दर्जनों लोगों को कथित तौर पर झूठे दावे दायर करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है।

इस्साइली हमले में गाजा में दो बच्चों समेत पांच की मौत, आईडीएफ का दावा-हमास के ठिकाने को बनाया निशाना

गाजा, एजेंसी। इस्साइल और हमास के बीच संघर्ष विराम को करीब दो माह का समय बीतने वाला है, लेकिन अभी भी तनाव बना हुआ है और संघर्ष विराम के बाद भी कई बार दोनों पक्ष एक दूसरे पर हमले के आरोप लगा चुके हैं। ताजा इस्साइली हमले में गाजा में दो बच्चों समेत पांच की मौत हो गई है। गाजा सिविल डिफेंस एजेंसी ने इसकी पुष्टि की है। वहीं इस्साइल का दावा है कि हमास के लड़ाकों ने उसके सैनिकों पर हमला किया, जिसमें उसके पांच सैनिक घायल हो गए। गाजा की सिविल डिफेंस एजेंसी ने बताया कि इस्साइली मिसाइल हमले में पांच नागरिकों की मौत हुई है, जिनमें दो बच्चे शामिल हैं। कई अन्य लोग घायल भी हुए हैं। घायलों में कई की हालत गंभीर है। यह हमला हजार यूनिट्स के पश्चिम में स्थित अल मवासी में हुआ। एजेंसी ने बताया कि कुवैत के फील्ड अस्पताल के पास स्थित शरणार्थी कैंप में यह हमला हुआ। गाजा के एक अस्पताल ने भी हमले में पांच लोगों की मौत की पुष्टि की है। मरने वालों में आठ और 10 साल के दो बच्चे भी शामिल हैं। अस्पताल ने बताया कि हमले में 32 लोग घायल हुए हैं। वहीं इस्साइली सेना ने बयान जारी कर कहा कि दक्षिणी गाजा में ‘हमास के आतंकियों’ ने उनके जवानों पर घात लगाकर हमला किया, जिसमें पांच जवान घायल हो गए।

विदेश मंत्री रूबियो बोले- अधिक क्षेत्रों पर नियंत्रण चाहता है इस्लामी कट्टरपंथ, अमेरिका के लिए तत्काल खतरा

वॉशिंगटन डीसी, एजेंसी। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने बुधवार को चेतावनी दी कि इस्लामी कट्टरपंथ का मकसद अधिक क्षेत्र और लोगों पर नियंत्रण पाना है। उन्होंने कहा कि यह दुनिया के लिए ‘तत्काल खतरा’ है। उन्होंने कहा कि अमेरिका उन लोगों के लिए बीजा पर प्रतिबंध लगाना चाहिए, जो नाज़ीरिया और दुनियाभर के ईसाइयों के खिलाफ हिंसा को समर्थन या वित्तीय मदद देते हैं।

‘अधिक क्षेत्र पर नियंत्रण चाहता है इस्लामी कट्टरपंथ’ : रूबियो ने फोक्स न्यूज से साक्षात्कार दिया। इसमें उन्होंने कहा कि अमेरिका को सबसे बड़ा खतरा इस्लामी कट्टरपंथ से है। उनके

अमेरिका में एफ-16 फाइटर जेट क्रैश जमीन से टकराते ही आग लगी

कुछ सेकेंड पहले पायलट सुरक्षित निकला

वॉशिंगटन डीसी, एजेंसी। अमेरिका में गुरुवार को यूएस एयरफोर्स का एक एफ-16 लड़ाकू विमान क्रैश हो गया। हादसे से कुछ सेकेंड पहले पायलट सुरक्षित बाहर निकल गया, जिससे उसकी जान बच गई। हादसा लोकल टाइम के मुताबिक सुबह करीब 10:45 बजे दक्षिणी कैलिफोर्निया में ट्राना शहर के एक रेगिस्तान में हुआ। विमान ट्राना एयरपोर्ट से करीब तीन किलोमीटर दूर गिरा। एयरपोर्ट मैनेजर ने बताया कि इस इलाके में अक्सर मिलिट्री विमान उड़ते रहते हैं। सोशल मीडिया पर आए वीडियो में देखा गया कि विमान तेजी से नीचे गिर रहा था और पायलट पैराशूट के सहारे बाहर निकल आया। जमीन से टकराते ही विमान में बड़ा धमाका हुआ और काला धुआं आसमान में भर गया।

एफ-16 की कीमत 1.70 हजार करोड़ रुपए

एयरफोर्स के 2021 के डेटा के मुताबिक एक एफ-16 फाइटिंग फाल्कन की कीमत लगभग 18.8 मिलियन डॉलर (करीब 1.70 हजार करोड़ रुपए) है। यह एयरक्राफ्ट थंडरबर्ड्स स्क्वाड्रन का था। यह टीम लास वेगास के पास नैलिस एयरफोर्स बेस से काम करती है और अपने एयर शो और खतरनाक स्टंट्स के लिए दुनियाभर में जानी जाती है। थंडरबर्ड्स टीम ने बताया कि ट्रेनिंग मिशन के दौरान पायलट विमान से सफलतापूर्वक बाहर निकल गया। पायलट को मामूली चोटें आईं और उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। लोकल फायर ब्रिगेड डिपार्टमेंट ने बताया कि घटनास्थल पर सिर्फ पायलट मौजूद था और आग से आसपास के इलाके को कोई खतरा नहीं है।

क्रैश का कारण अभी साफ नहीं

अधिकारियों के मुताबिक सुबह 6 थंडरबर्ड्स जेट

पद संभालने के 22 दिन बाद ही मधेश प्रदेश के सीएम सरोज का इस्तीफा, विश्वास मत से पहले छोड़नी पड़ी कुर्सी

काठमांडो, एजेंसी। नेपाल के मधेश प्रदेश में जारी सत्ता संकट मंगलवार को एक नए मोड़ पर पहुंच गया। पद संभालने के 22 दिन बाद ही मुख्यमंत्री सरोज कुमार यादव को इस्तीफा देना पड़ा। विश्वास मत हासिल करने के लिए उनके पास संख्या बल कम पड़ गया था। सुप्रीम कोर्ट ने सरोज यादव को प्रदेश सभा का विश्वास मत हासिल करने का निर्देश दिया था। विश्वास मत हासिल होने की संभावना बेहद कम दिखने के बाद यादव ने प्रदेश सभा की बैठक में ही अपना इस्तीफा पेश कर दिया। विपक्षी दलों की अनुपस्थिति ने शक्ति परीक्षण को अंशुभव बना दिया था। बैठक में केवल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले) के विधायक मौजूद थे। सरकार में शामिल राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी की मंत्री कंचन बिच्छा व नेपाल संघीय समाजवादी पार्टी की मंत्री बिमला अंसारी भी उपस्थित थे।

विश्वास मत पर उठाए सवाल

अपने इस्तीफे से पहले सरोज यादव ने आरोप लगाया कि उनकी नियुक्ति बाध्य



तेहरान, एजेंसी। इस्लामी के सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह अली खामेनेई ने देश महिलाओं के लिए लागू सख्त ड्रेस कोड का पुरजोर समर्थन करते हुए इसे जायज ठहराया है। इस दौरान खामेनेई ने पश्चिमी देशों पर गंभीर आरोप लगाते हुए पश्चिमी संस्कृति को महिलाओं की गरिमा को ठेस पहुंचाने का जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने कहा है कि इस्लाम

इस्लाम महिलाओं को आजादी के साथ जीने का अवसर देता है: खामेनेई

महिलाओं को आजादी के साथ जीने का अवसर देता है, वहीं पश्चिमी देशों में औरतों को महज भोग की वस्तु समझा जाता है। इससे पहले हाल ही में ईरान की संसद के आधे से अधिक सदस्यों ने न्यायपालिका पर हिजाब कानून को लागू करने में विफल रहने का आरोप लगाया है। एक दिन बाद आयतुल्लाह अली खामेनेई ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स इससे जुड़े कई पोस्ट किए। खामेनेई ने यह बताने की कोशिश की है कि अनिवार्य हिजाब कानून और ड्रेस-कोड नैतिक रूप से पश्चिम से बेहतर है।

पश्चिमी संस्कृति पर हमला

खामेनेई ने हिजाब कानून के समर्थन में तर्क देते हुए कहा कि किसी भी समाज

अफगानिस्तान : 13 लोगों के हत्यारे को मारी गई गोली

खोस्त, एजेंसी। अफगानिस्तान के खोस्त शहर में तालिबान प्राधिकारियों ने एक ही परिवार के 13 लोगों की हत्या में सजा पा चुके एक व्यक्ति को सार्वजनिक रूप से मौत की सजा दिलावाई। पीड़ित परिवार के ही एक व्यक्ति ने सबके सामने दोषी को गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया।

तालिबान के शासन में सार्वजनिक तौर पर दी गई मौत की सजा का यह 11वां मामला है। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से मौत की सजा सुनाए जाने के बाद मंगलवार को दोषी व्यक्ति को मृत्युदंड दिया गया। खोस्त के स्पोर्ट्स स्टेडियम में बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हुए थे, जिनमें पीड़ित के परिजन भी शामिल थे। एक अपील कोर्ट और खुद टैप कोर्ट की तरफ से मौत की सजा सुनाए जाने और सुप्रीम लीडर हिबतुल्लाह अखुंदजादा की मंजूरी के बाद मृत्युदंड का निर्देश दिया गया।

अल्जीरियाई कोर्ट ने फ्रेंच पत्रकार क्रिस्टोफ ग्लेज की 7 साल की सजा बरकरार रखी

अल्जीयर्स, एजेंसी। अल्जीरिया की एक अपील कोर्ट ने बुधवार को एक फ्रेंच स्पोर्ट्स राइटर की सात साल की जेल की सजा बरकरार रखी, जिसे ‘आतंकवाद का महिमामंडन’ करने का दोषी पाया गया था, जिससे उसकी जल्दी रिहाई की उम्मीदें खत्म हो गईं। क्रिस्टोफ रलीजेस को छह महीने पहले एक फुटबॉल अधिकारी के साथ इंटरव्यू के लिए सजा सुनाई गई थी, जिस पर एक बैन अलगाववादी आंदोलन से संबंध होने का आरोप था। उन्हें अल्जीरिया के आतंकवाद-रोधी कानूनों का उल्लंघन करने और प्रोपेगंडा के लिए पब्लिकेशन रखने का दोषी पाया गया था, इस मामले को राइट्स ग्रुप और फ्रेंच मीडिया ने कड़ी आलोचना की थी।

अमेरिका में पाकिस्तानी मूल का व्यक्ति बंदूकों और गोला-बारूद के साथ गिरफ्तार

स्कूल पर हमले की रची थी साजिश

डेलावेयर, एजेंसी। पाकिस्तान के एक प्रवासी को कथित तौर पर बंदूकों, गोला-बारूद, शरीर के कवच (बॉडी आर्मर) के साथ गिरफ्तार किया गया है। उसके पास से एक नोटबुक भी बरामद की गई है, जिसमें उसने स्कूल परिसर में सामूहिक गोलीबारी में ‘सभी को मारने’ और ‘शहीद’ होने की योजना बनाई थी। गिरफ्तार व्यक्ति डेलावेयर विश्वविद्यालय का पूर्व छात्र है। न्यूयॉर्क पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक, व्यक्ति की पहचान लुकमान खान (25 वर्षीय) के रूप में हुई। उसे 24 नवंबर की रात गिरफ्तार किया गया। पुलिस को वह एक पार्क में उसके ट्रक पर मिला और उसके व्यवहार पर शक होने के बाद वाहन की तलाशी ली। ट्रक में एक रॉलिंग पिस्तौल, 27-राउंड गोलियों के मैगजिन और बॉडी आर्मर की प्लेटें बरामद हुईं। पिस्तौल को ऐसे किट में रखा गया था, जिसे जोड़कर उसे सेमी-ऑटोमैटिक राइफल बनाया जा सकता था। हथियारों के साथ पुलिस को एक नोटबुक भी मिली, जिसमें हाथ से जानकारी लिखी गई थी। इसमें लिखा गया था कि वह अपने पुराने स्कूल परिसर में हथियारों का इस्तेमाल करके गोलीबारी कैसे करेगा।

नोटबुक में था मुख्यालय का नक्शा : रिपोर्ट के मुताबिक, नोटबुक में विश्वविद्यालय के प्रशासनिक भवन (मुख्यालय) का



नक्शा भी था, जिसमें प्रवेश और निकासी के रास्ते चिह्नित किए गए थे। इसमें ‘सभी को मारो,’ ‘शहीद’ जैसे शब्द लिखे थे और बताया गया था कि गोलीबारी के बाद पुलिस से कैसे बचा जाए। पुलिस ने कहा कि यह पूरी योजना पहले से बनाई गई थी और इसमें साफ तौर पर युद्ध जैसे तरीकों का इस्तेमाल किया जाना था। हालांकि, हमले की साजिश के पीछे कारण स्पष्ट नहीं हैं। लुकमान ने गिरफ्तारी के बाद पुलिस को बताया कि शहीद होना ‘सबसे महान चीजों में से एक है’।

पाकिस्तान में हुआ था लुकमान का जन्म : न्यू कैसल काउंटी पुलिस ने न्यूयॉर्क पोस्ट को बताया, पाकिस्तान में जन्मा लुकमान खान बचपन से ही अमेरिका में रह रहा था और अमेरिकी नागरिक है। खान पर मशीन गन अवैध रूप से रखने का आरोप लगाया गया है और एफबीआई की जांच जारी है। पड़ोसियों ने जांचकर्ताओं को बताया कि पहले खान मिलनसार बनकर था। लेकिन पिछले कुछ महीनों से वह लोगों से अलग-थलग रहने लगा था।

मुझे लगता है कि हमें उत्तर कोरिया से माफी मांगनी चाहिए लेकिन... फिर रुक गए साउथ कोरिया के राष्ट्रपति?

सियोल, एजेंसी। दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति ली जे म्युंग ने बुधवार को कहा कि वह पिछली सरकार द्वारा उत्तर कोरिया में सरकार के खिलाफ पंचें बांटने के लिए ड्रोन भेजने के आरोप पर उत्तर कोरिया से माफी मांगना चाहते हैं, हालांकि मौजूदा घरेलू राजनीतिक माहौल में ऐसा करना मुश्किल है। ली ने चेओंग वा डे में विदेशी संवाददाताओं के साथ विशेष बातचीत में यह बात कही। जब उनसे पूछा गया कि क्या वह इस कार्रवाई के लिए राज्य स्तर पर माफी जारी करने के बारे में सोच रहे हैं ताकि कोरिया के बीच तनाव कम करने में



मदद मिल सके, तो ली ने कहा कि अगर मेरा मन पढ़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि एक तरफ, मुझे लगता है कि हमें माफी मांगनी चाहिए, लेकिन दूसरी तरफ मुझे चिंता है कि (माफी) राजनीतिक और विचारधारा के टकराव का मुद्दा बन सकता है, जहां सरकार को उत्तर कोरिया का समर्थक कहा जाएगा। ली का यह बयान ड्रोन

मामले में एक विशेष जांच के बीच आया है। ली से पहले के राष्ट्रपति यून सुक येओल और सेना में उनके कुछ करीबी साथियों ने कथित तौर पर अक्टूबर 2024 में प्योंगयांग में उत्तर कोरिया के लीडर किम जोंग-उन की बुराई करने वाले पत्रों ले जाने वाले ड्रोन तैनात करने का ऑर्डर दिया था, ताकि उत्तर कोरिया को जवाबी कार्रवाई के लिए उकसाया जा सके और इसे मार्शल लॉ लागू के बहाने के तौर पर इस्तेमाल किया जा सके। ली ने उत्तर-कोरियाई संबंधों पर कहा कि ये इतने बंद हैं कि एक सूई के बराबर जगह भी नहीं बची है। उन्होंने

इस बात पर जोर दिया कि बातचीत के रास्ते फिर से खोलने के लिये सियोल के एकतरफा विश्वास-निर्माण उपाय जरूरी हो सकते हैं। राष्ट्रपति ने दक्षिण कोरिया-अमेरिका के संयुक्त सैन्य अभ्यास के लंबे समय से चले आ रहे मुद्दे पर समझौता करने की इच्छा का भी संकेत दिया। उन्होंने कहा कि अगर अमेरिका-उत्तर कोरिया की बातचीत को फिर से शुरू करने के लिये जरूरी हुआ तो वह इन सैन्य अभ्यासों को कम करने के लिये भी तैयार हैं। ली ने इस बात पर जोर दिया कि उत्तर कोरिया के फैसले लेने की प्रक्रिया पर अमेरिका का ज्यादा असर है।

खोस्त, एजेंसी। अफगानिस्तान के खोस्त शहर में तालिबान प्राधिकारियों ने एक ही परिवार के 13 लोगों की हत्या में सजा पा चुके एक व्यक्ति को सार्वजनिक रूप से मौत की सजा दिलावाई। पीड़ित परिवार के ही एक व्यक्ति ने सबके सामने दोषी को गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया। तालिबान के शासन में सार्वजनिक तौर पर दी गई मौत की सजा का यह 11वां मामला है। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से मौत की सजा सुनाए जाने के बाद मंगलवार को दोषी व्यक्ति को मृत्युदंड दिया गया। खोस्त के स्पोर्ट्स स्टेडियम में बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हुए थे, जिनमें पीड़ित के परिजन भी शामिल थे। एक अपील कोर्ट और खुद टैप कोर्ट की तरफ से मौत की सजा सुनाए जाने और सुप्रीम लीडर हिबतुल्लाह अखुंदजादा की मंजूरी के बाद मृत्युदंड का निर्देश दिया गया।

पाकिस्तान बेचेगा सरकारी एयरलाइंस, ‘इज्जत नीलामी’ में बोली लगाएगी आसिम मुनीर की फौजी कंपनी

इस्लामाबाद, एजेंसी। कर्ज के बोझ और आईएमएफ की सख्त शर्तों से जकड़ा कंगाल पाकिस्तान अब अपनी राष्ट्रीय एयरलाइन पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस (पीआईए) को बेचने जा रहा है। प्री-क्वालिफाइड चार बोलियों में फौजी फर्टिलाइजर कंपनी लिमिटेड भी शामिल है, जो पाकिस्तानी सेना के नियंत्रित फौजी फाउंडेशन का हिस्सा है। प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के हवाले से जारी बयान में कहा गया है कि पीआईए की बोली 23 दिसंबर 2025 को होगी और इसका सभी मीडिया चैनलों पर लाइव प्रसारण किया जाएगा। डॉन अखबार के मुताबिक, पीआईए में 51 से 100 प्रतिशत तक हिस्सेदारी का विनिवेश आईएमएफ के 7 अरब डॉलर के नए बेलआउट पैकेज की प्रमुख शर्तों में से एक है।

जियो टीवी की रिपोर्ट के अनुसार, निजीकरण मंत्री मुहम्मद अली ने पिछले महीने रॉयटर्स को बताया था कि इस साल निजीकरण से 86 अरब रुपये की कमाई का लक्ष्य रखा गया है। पीआईए की ऑटिस बोली में कुल आय का सिर्फ 15 प्रतिशत हिस्सा सरकार को मिलेगा, बाकी खरीदार कंपनी के पास रहेगा। डॉन के अनुसार, पीआईए का विनिवेश पिछले दो दशकों में पाकिस्तान का पहला बड़ा निजीकरण कदम होगा।

बिक्री के लिए चार बोलियों को प्री-क्वालिफाइड किया गया है...लकी सीमेंट कंसोर्टियम, ऑफिश हबीब कॉर्पोरेशन कंसोर्टियम, फौजी फर्टिलाइजर कंपनी लिमिटेड, एयर ब्लू लिमिटेड। बता दें कि फौजी फर्टिलाइजर, फौजी फाउंडेशन का

हिस्सा है, जो आज पाकिस्तान का सबसे बड़ा कॉर्पोरेट साम्राज्य बन चुका है। उस देश में जहां सैन्य का हर क्षेत्र में दखल है, मौजूदा सबसे ताकतवर शक्तिशाली आर्मी चीफ जनरल अशिम मुनीर फौजी फाउंडेशन के सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में सीधे तौर पर शामिल नहीं हैं, लेकिन वे क्वार्टरमास्टर जनरल की नियुक्ति करते हैं, जो फाउंडेशन के बोर्ड का अहम सदस्य होता है। इस तरह जनरल मुनीर संस्थागत नियंत्रण के जरिए फौजी फाउंडेशन पर अप्रत्यक्ष रूप से पूरा प्रभाव रखते हैं। पीआईए का विनिवेश पाकिस्तान को लिये इसकी ही अहम है क्योंकि वह

कर्ज चुकाने के लिए नया कर्ज लेता रहता है। 2023 में वर्षों की वित्तीय कुप्रबंधन की वजह से वह डिफॉल्ट के मुहाने पर खड़ा था। उसका सबसे बड़ा खर्च रक्षा बलों पर होता है। आईएमएफ का 7 अरब डॉलर का नया प्रोग्राम सितंबर 2024 में मंजूर हुआ था, जिसमें 1 अरब डॉलर तुरंत मिला, बाकी राशि तीन साल में मिलनी है। अपनी लड़खड़ाती अर्थव्यवस्था के साथ पाकिस्तान आज आईएमएफ का पांचवां सबसे बड़ा कर्जदार देश है और 1958 से अब तक उसने आईएमएफ से 20 से ज्यादा बार कर्ज लिया है।

गौरतलब है कि पीआईए कई सालों से गहरे वित्तीय संकट में है। 2023 में नवंबर महीने के 7000 कर्मचारियों को वेतन तक नहीं मिला था। उससे पहले 2020 में यूरोपीय संघ ने सुरक्षा मानकों में खामियों की वजह से पीआईए की उड़ानों पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया था।

एसआईआर को लेकर अखिलेश की योगी से मांग... किसी भी बीएलओ पर दबाव नहीं डाले



लखनऊ (एजेंसी)। समाजवादी पार्टी (सपा) अध्यक्ष और पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश सरकार से मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के अब तक हुए काम को प्रकाशित करने और सुनिश्चित करने की मांग की कि बूथ स्तरीय अधिकारियों (बीएलओ) पर ‘जानलेवा दबाव’ न डाला जाए। अखिलेश यादव ने मांग की कि राज्य में एसआईआर का जितना भी काम हुआ है, उसका आकड़ा प्रकाशित करें। उन्होंने कहा, बीएलओ पर जानलेवा दबाव हटाकर अतिरिक्त अधिकृत लोगों को समयावधि के अनुरूप काम पर लगाया जाए।’ यादव ने कहा कि सुनिश्चित किया जाए कि सप्ताधारियों के दल और उनके संगी-साथी पिछले दरवाजे से इस काम में अब नहीं हैं और न आगे कभी होने वाले हैं।

बेंगलुरु के मेट्रो स्टेशन पर व्यक्ति ने ट्रेन के सामने कूदकर कथित तौर पर आत्महत्या की

बेंगलुरु (एजेंसी)। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु के केंगरी मेट्रो स्टेशन पर एक व्यक्ति ने ट्रेन के सामने कूदकर कथित तौर पर आत्महत्या की। जिससे पर्पल लाइन पर मेट्रो सेवाएं कुछ देर के लिए रुक गईं। मेट्रो अधिकारियों ने बताया कि मृतक की पहचान 38 वर्षीय शांतगोड़ पुलिसपटिल के रूप में हुई है। यह घटना सुबह सावा आठ बजे हुई। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, शांतगोड़ ने ट्रेन से टकराने के लिए सही समय पर छलांग लगाई थी और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने पैरामेडिकल टीम के साथ मिलकर शव को तुरंत पटरियों से हटाया। इस घटना के बाद पर्पल लाइन पर मैसूर रोड से वल्लभगुड तक सेवाएं अस्थायी रूप से निलंबित कर दी गईं। अधिकारियों ने बताया कि बाद में सेवाओं को बहाल किया गया। बेंगलोर मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (बीएमआरसीएल) ने कहा, ‘‘सुबह 9-40 बजे तक ज्ञान भारती और वल्लभगुड के बीच की सेवाएं पूरी तरह से बहाल कर दी गई हैं। अब पूरे पर्पल लाइन पर ट्रेन परिचालन सामान्य समय-सारणी के अनुसार हो रहा है।’’

राहुल गांधी की सांसदी को चुनौती देने वाली याचिका हाईकोर्ट ने की खारिज

लखनऊ (एजेंसी)। यूपी में हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को लोकसभा चुनाव से अयोग्य करार देने के आग्रह वाली याचिका खारिज कर दी है। न्यायमूर्ति शेखर बी सराफ और न्यायमूर्ति मंजीव शुक्ला की खंडपीठ ने यह फैसला स्थानीय अधिका आशोक पांडेय की याचिका पर दिया। याची ने इस आधार पर राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता खत्म करके आग्रह किया था कि गुजरात की एक अदालत से मानहानि के केस में उन्हें सजा सुनाई गई थी, इसलिए वह सांसद के रूप में अयोग्य थे। कोर्ट ने कहा कि राहुल गांधी की सजा पर सुप्रीम कोर्ट ने 2023 में ही रोक लगा दी थी। ऐसे में राहुल की अयोग्यता अमल में नहीं है। ऐसे में याचिका खारिज की जाती है।

तीन वर्ष की बच्ची से दुष्कर्म करने वाले को आजीवन सश्रम कारावास

कुशीनगर (एजेंसी)। कुशीनगर की एक विशेष ‘पॉवर्स’ अदालत ने एक व्यक्ति को पांच साल से अधिक समय पहले 3 साल की बच्ची से बलात्कार करने के जुर्म में आजीवन कारावास की सजा सुनाई। यौन अपराध से बच्चों का संरक्षण (पॉवर्स) अधिनियम के तहत विशेष अदालत ने दोषी पर पांच लाख का जुर्माना लगाया। सहायक जिला शासकीय अधिका फूलबदन व अजय गुप्ता ने बताया कि अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश दिनेश कुमार ने मामले में सत्येन्द्र को दोषी करार देकर कहा कि आरोपी को सभ्य समाज में रहने की अनुमति नहीं दी जा सकती, क्योंकि मौका मिलने पर वह किसी अन्य मासूम बच्चे को भी अपना शिकार बना सकता है। अदालत ने कहा कि तीन साल की बच्ची से ऐसा जबरन कृत्य करने वाला व्यक्ति अधिकतम सजा का हकदार है। सरकारी वकील ने अदालत को बताया कि वादी ने 23 जून 2020 को नेबुआ नौरंगिया थाने में सूचना दी कि आरोपी आम खिलाने के बहाने उनकी तीन वर्ष की बच्ची को अपने घर ले गया। घर में कोई नहीं था, जहां उसने बच्ची से दुष्कर्म किया। इधर बच्ची को दूढ़ने निकली उसकी मां को लोगों ने बताया कि उन्होंने बच्ची को सत्येन्द्र संग जाते देखा था।

गूगल पर 2025 में सबसे ज्यादा कुंभमेले के बाद धर्मद को किया गया सर्च

नई दिल्ली (एजेंसी)। गूगल ने 2025 के सबसे ज्यादा सर्च किए गए न्यूज इवेंट की सूची जारी की है। इस लिस्ट में कुंभ मेले के बाद धर्मद सबसे ज्यादा सर्च किए गए। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक पहले नंबर पर सबसे ज्यादा महाकुंभ मेला सर्च किया गया। इसके बाद दूसरे नंबर पर धर्मद, तीसरे नंबर पर बिहार इलेक्शन, चौथे पर भारत-पाकिस्तान न्यूज और पांचवें नंबर पर दिल्ली इलेक्शन रिजल्ट सर्च किया गया। रिपोर्ट के मुताबिक धर्मद को लेकर पांच वीजें सबसे ज्यादा सर्च गईं। सबसे पहले तो लोग ये जानना चाहते थे कि धर्मद जिंदा हैं या नहीं। दरअसल, धर्मद के निधन से 10-15 दिन पहले ही उनकी मौत की खबर आई थी, जिसे हेमा मालिनी और ईशा देओल ने खारिज कर दिया था। दूसरे नंबर पर धर्मद की हेल्थ अपडेट सर्च की गई। तीसरे नंबर पर धर्मद की न्यूज अपडेट सर्च किया गया। चौथे नंबर पर लोगों ने सर्च किया कि क्या धर्मद आज जिंदा हैं। इसके अलावा लोगों ने धर्मद की मौत का कारण भी सर्च किया। बता दें धर्मद अपने आखिरी समय में काफी बीमार थे। उन्हें मुंबई में अस्पताल में रखा गया था। उन्हें वेंटीलेटर पर भी पिंपट किया गया था। जब वो हॉस्पिटल में थे तभी उनकी डेथ की फेक खबर आई थी। हालांकि, परिवार ने इन खबरों को गलत बताया था।

उत्तर भारत में ठंड, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान के इलाके शीतलहर की चपेट में -जम्मू-कश्मीर और ऊपरी इलाकों में हल्की बारिश और बर्फबारी की संभावना

नई दिल्ली (एजेंसी)। पूरा उत्तर भारत ठंड की चपेट में है। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और आसपास के इलाकों में शीतलहर चल रही है। दिल्ली-एनसीआर में पिछले दो दिनों से तापमान 5 डिग्री सेल्सियस के आसपास है। मौसम विभाग ने बताया कि जम्मू-कश्मीर से लेकर पंजाब-हरियाणा तक बने पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से उत्तर भारत में ठंड बढ़ने की संभावना है। वहीं, यूपी के भी कई इलाके शीतलहर के चपेट में हैं। मौसम विभाग ने बताया कि कई इलाकों में सुबह कोहरे के साथ तापमान 5 डिग्री के आसपास बना हुआ है। रिपोर्ट के मुताबिक बिहार में अभी न्यूनतम तापमान 11-12 डिग्री सेल्सियस तक बना हुआ है, जबकि अधिकतम तापमान 22 से 27 डिग्री के आसपास है। हालांकि, ग्रामीण इलाकों समेत पंजाब, हरियाणा से लेकर आसपास के क्षेत्रों में शीतलहर की स्थिति बनी हुई है। मौसम विभाग ने

बताया कि इन हिस्सों में पश्चिमी विक्षोभ की वजह से आसमान में बादल घिरे हुए हैं, हालांकि, किसी प्रकार के बारिश का कोई अलर्ट नहीं है। वहीं इसकी वजह से पहाड़ी से मैदानी इलाकों की ओर चलने वाली तेज हवाएं शीतलहर की स्थिति की और भी गंभीर बना रही है। मौसम विभाग की रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली-एनसीआर के साथ-साथ कई जगहों पर न्यूनतम तापमान सामान्य से 4-5 डिग्री सेल्सियस नीचे है, जिसके कारण शीतलहर की स्थिति बनी हुई है। जम्मू-कश्मीर में पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय है। इस वजह से आसपास के इलाकों में बादल छाए हैं। हालांकि, पहाड़ी या मैदानी इलाकों में बारिश या बर्फबारी की चेतावनी जारी की गई है। एक और कमजोर पश्चिमी विक्षोभ 5 दिसंबर को पश्चिमी हिमालय की ओर बढ़ रहा है और पहाड़ों को पार करने में इसे करीब 24 से 36 घंटे लगेंगे। इस दौरान

निचले इलाकों पंजाब, हरियाणा और दिल्ली के आसपास ठंड का असर बढ़ने की संभावना है।

पहाड़ों पर पश्चिमी विक्षोभ की वजह से जम्मू-कश्मीर और ऊपरी इलाकों में हल्की बारिश और बर्फबारी हो सकती है। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान के कुछ हिस्सों में शीतलहर की स्थिति बने रहने की संभावना है। वहीं, पूर्वी उत्तर प्रदेश में एक इंड्यूस्ड साइक्लोनिक सर्कुलेशन की स्थिति से कोहरे और ठंड की संभावना बढ़ गई है। मौसम विभाग ने बताया कि नॉर्थ ईस्ट के राज्यों के कुछ हिस्सों में घना कोहरा पड़ सकता है। वहीं, तमिलनाडु, तटीय आंध्र प्रदेश, केरल, लक्षद्वीप और दक्षिण कर्नाटक में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है।

यूपी के कई इलाके शीतलहर की चपेट में हैं। वहीं, राज्य के कई हिस्से घने कोहरे से घिरे हैं। सुबह शाम कड़ाके की ठंड से लोगों का हाल



बेहाल है, हालांकि, दिन निकलने के बाद धूप खिलने की वजह से लोगों को राहत है। वहीं, बिहार में मौसम अभी शुष्क बना हुआ है। राज्य में न्यूनतम तापमान 11 से 12 डिग्री सेल्सियस के आसपास है। वहीं, अधिकतम तापमान 22 से 27 डिग्री के आसपास बना है। पहाड़ों पर एंफ्रिट पश्चिमी विक्षोभ का असर जल्द ही दिखेगा। गलन वाली सर्दी पड़ सकती है।

सुप्रीम कोर्ट ने अरुंधति रॉय की किताब पर रोक लगाने की मांग को खारिज किया

नई दिल्ली (एजेंसी)। सुप्रीम कोर्ट ने अरुंधति रॉय की नई किताब मदर मेरी कप्पट 2 मी की बिस्ती और प्रचार पर रोक लगाने की मांग वाली जनहित याचिका को खारिज किया है। याचिकाकर्ता ने किताब के कवर पेज पर अरुंधति रॉय को सिगरेट पीते हुए दिखाए जाने पर आपत्ति जाहिर की थी। यह सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद अधिनियम 2003 (सीओटीपीए, 2003) का उल्लंघन है और धूम्रपान को बढ़ावा देता है, जबकि कानून के अनुसार चेतावनी के बिना इस तरह के चित्र का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। मामले की सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायाधीश यूएफका की अध्यक्षता वाली पीठ ने याचिका खारिज की। अदालत ने कहा कि अरुंधति रॉय एक जानी-मानी लेखिका हैं और उन्होंने किसी भी प्रकार से धूम्रपान का प्रमोशन नहीं किया है। किताब में आवश्यक चेतावनी भी मौजूद है, और किसी साहित्यिक कृति के कवर पेज को धूम्रपान के प्रचार के



बराबर नहीं माना जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने केरल हाईकोर्ट के पहले के आदेश में दखल देने से इनकार कर दिया, जिसने भी रोक लगाने से मना कर दिया था। यह जनहित याचिका अधिका राजसिंहन ने दायर की थी। उन्होंने स्पष्ट किया कि आपत्ति केवल कवर पर सिगरेट वाले चित्र से थी, क्योंकि यह धूम्रपान को बौद्धिकता और रचनात्मकता के प्रतीक के रूप में प्रस्तुत करता है और युवा पाठकों को गुमराह कर सकता है। अदालत ने यह भी माना कि सीओटीपीए, 2003 का नियम (पैकेज पर चेतावनी छपना) विशुद्ध रूप से तंबाकू उत्पादों के पैकेट पर लागू होता है, किताबों पर नहीं।

संचार साथी’ ऐप बना चैंपियन, डाउनलोड में एप्पल, गूगल ऐप को पीछे छोड़ बना नंबर वन

-विरोध के बावजूद दूरसंचार विभाग ने ऐप इंस्टॉल करने का अपना आदेश वापस लिया

नई दिल्ली (एजेंसी)। विपक्ष, मोबाइल कंपनियों और नागरिक समाज के विरोध के बाद, दूरसंचार विभाग ने सभी मोबाइल फोन में ‘संचार साथी’ ऐप पहले से इंस्टॉल करने का अपना आदेश वापस ले लिया है, लेकिन इसका नतीजा यह हुआ कि जिस ऐप को पहले नजरअंदाज किया जाता था वह अचानक सुविधियों में आ गया।

मीडिया रिपोर्ट में सेंसर टावर के आंकड़ों के मुताबिक संचार साथी ऐप जो 29 नवंबर को भारत में सबसे ज्यादा डाउनलोड किया गया ऐसे में 127वें स्थान पर था वह 2 दिसंबर को ऐपल ऐप स्टोर पर गूगल जेमिनाई और चैटजीपीटी को पीछे छोड़ते हुए पहले पायदान पर पहुंच गया। सरकार द्वारा 3 दिसंबर को आदेश वापस लेने के बाद भी यह शीर्ष स्थान पर बना हुआ है। ऐप गुरुवार तक उस स्थान पर बना रहा। उत्पादकता श्रेणी के भीतर, यह 1 दिसंबर के 15 वें स्थान से बढ़कर 3 दिसंबर को दूसरे पायदान पर पहुंच गया और अब शीर्ष स्तर पर बना हुआ है।

उद्योग विशेषज्ञों का कहना है कि ऐप के बारे में जिज्ञासा तब बढ़ी जब गोपनीयता से जुड़ी संभावित चिंता पर बहस शुरू हुई और इसके कारण ही डाउनलोड में वृद्धि हुई। कुछ विश्लेषी



नेताओं का दावा है कि बीजेपी कार्यकर्ताओं ने निदेश को समर्थन देने की बात दिखाते के लिए बड़ी संख्या में ऐप डाउनलोड किए और उनका यह तर्क है कि डाउनलोड में यह तेजी अस्थायी साबित हो सकती है।

मोबाइल उपकरण निर्माताओं ने चेतावनी दी कि इस तरह की चीजें लागू करने से एक मिसाल कायम हो सकती है, जिससे अन्य मंत्रालय या राज्य सरकारें भी अपने संबंधित ऐप इंस्टॉल के लिए यही मांग करने के लिए



प्रोत्साहित हो सकते हैं। कंपनियों ने यह भी बताया कि भारत बड़ी संख्या में फोन निर्यात करता है जिसका अर्थ यह है कि अनिवार्य रूप से इंस्टॉल करने के लिए घरेलू और निर्यात वाले उपकरणों के लिए अलग-अलग उत्पादन की जरूरत हो सकती है जिससे निर्माण प्रक्रिया और जटिल हो सकती है। हालांकि, डीओटी ने 3 दिसंबर को निदेश वापस लेने के फैसले का बचाव करते हुए कहा कि उसने डाउनलोड में वृद्धि देखने के बाद कार्रवाई की।

पुतिन के भारत दौरे पर थरूर ने दिया संदेश बोले- अब किसी को कोई गलतफहमी नहीं होना चाहिए

नई दिल्ली (एजेंसी)। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन गुरुवार शाम को चार साल बाद पहली बार दो दिवसीय राज्य यात्रा पर नई दिल्ली पहुंचे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एयरपोर्ट पर उन्हें व्यक्तिगत रूप से गर्मजोशी से स्वागत किया, जो कूटनीतिक रस्मों से इतर एक विशेष इशारा था। यह यात्रा 23वें भारत-रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन के लिए है, जो शुक्रवार को हैदराबाद हाउस में आयोजित होगा। पुतिन का यह दौरा यूक्रेन युद्ध के बाद उनका पहला भारत प्रवास है, जो वैश्विक अस्थिरता के बीच दोनों देशों की रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने का महत्वपूर्ण अवसर साबित हो रहा है। थरूर सांसद शशि थरूर ने इस दौर

ऊर्जा, रक्षा और सामरिक क्षेत्रों में रूस भारत का सबसे भरोसेमंद साझेदार रहा है। थरूर ने एक साक्षात्कार में जोर दिया, यह बहुत महत्वपूर्ण यात्रा है। वैश्विक राजनीति के उथल-पुथल भरे दौर में पुराने और विश्वसनीय साझेदारों के साथ रिस्ते और मजबूत करना जरूरी है। रूस के साथ हमारा संबंध हमको पुराना है, जो हाल के वर्षों में और प्रासंगिक हो गया। तेल-गैस आपूर्ति में रूस प्रमुख स्रोत है, जबकि रक्षा सहयोग का महत्व भी 2025 के ऑपरेशन सिट्दूर में एस-400 सिस्टम के जरिए पाकिस्तानी मिसाइलों से दिल्ली जैसे शहरों की रक्षा करते हुए साफ दिखा। थरूर ने भारत की विदेश नीति की कोजकर सराहना की। उन्होंने कहा कि रणनीतिक स्वातंत्रता पर फिर बल दिया।

उन्होंने स्पष्ट किया कि रूस के साथ मजबूत बंधन अमेरिका या चीन जैसे किसी अन्य देश के साथ संबंधों को प्रभावित नहीं करते। भारत अपनी संप्रभुता के आधार पर हितों और साझेदारियों का चयन करता है। किसी को यह ध्रम नहीं होना चाहिए कि रूस के साथ निकटता किसी अन्य राष्ट्र के खिलाफ है। उन्होंने उम्मीद जताई कि सम्मेलन में रक्षा उत्पादन, व्यापार, विज्ञान-प्रौद्योगिकी, ऊर्जा, संस्कृति और मानवीय सहयोग जैसे क्षेत्रों में कई समझौते होंगे, जो द्विपक्षीय संबंधों को नई ऊँचाई देंगे।

पूर्व भारतीय राजनयिक अरुण सिंह ने भी भारत-रूस संबंधों की निरंतर प्रासंगिकता पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि दशकों से मॉस्को ने राजनीतिक और रक्षा

क्षेत्र में भारत का साथ दिया है। बदलते वैश्विक परिदृश्य में भी रूस भारत की रणनीतिक प्राथमिकताओं में अहम स्थान रखता है। विशेषज्ञों का मानना है कि यह दौरा वैश्विक ध्रुवीकरण के बीच संतुलित कूटनीति और नई साझेदारियों की जरूरत को रेखांकित करता है। शुक्रवार को पुतिन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करेंगे, राजघाट पर महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि देंगे और रूसी चैनल आर्टी का भारत संस्करण लांच करेंगे। शाम को रवाना होने से पहले मोदी के साथ व्यापक वार्ता होगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और उनके रूसी समकक्ष एंड्रें बेलोसोव भी सैन्य सहयोग पर चर्चा करेंगे। अमेरिकी दूतावास और यूक्रेन शांति प्रयासों के बीच यह

बिहार की 53 जेलों में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर 9,073 नए सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे



पटना (एजेंसी)। बिहार राज्य के सभी जेलों के चप्पे-चप्पे पर अब खुफिया निगरानी रहेगी। उप मुख्यमंत्री सह गुहमंत्री सम्राट चौधरी ने बताया कि 53 जेलों में सुरक्षा व्यवस्था को अत्याधुनिक बनाने 9,073 नए सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। राज्य की आठ जेलों में पहले लगे कैमरों को नए लगाने वाले कैमरों से इंटीग्रेट किया जाएगा। इसके लिए 155 करोड़ 38 लाख 36 हजार 153 रुपये की स्वीकृति प्रदान की गई है। इस परियोजना से बिहार की जेल सुरक्षा व्यवस्था और मजबूत होगी। गुहमंत्री सम्राट ने बताया कि कारा एवं सुधार सेवाएं निरीक्षणालय को बेल्तान द्वारा उपलब्ध कराए गए संशोधित विस्तृत प्राक्कलन के आधार पर मंजूरी प्रदान की गई है। इस परियोजना में सीसीटीवी कैमरों, सॉफ्टवेयर, फील्ड इफास्ट्रक्चर, फाइबर नेटवर्क, स्थानीय मानीटरिंग व्यवस्था, पांच वर्षों के लिए संचालन एवं रखरखाव के लिए मेनपावर लागत, परामर्शी शुल्क, आकस्मिक व्यय तथा बेल्तान मार्जिन को भी सम्मिलित किया गया है। वित्तीय वर्ष 2025-26 के बजट प्रविधान के अंतर्गत इस योजना को मंजूरी प्रदान की गई है। मालूम हो कि गुह मंत्री का पदभार लेते ही सम्राट ने जेलों की निगरानी बढ़ाने का निर्देश अधिकारियों को दिया था। जेलों में कैदियों के पास से मोबाइल और बिना अनुमति बाहरी खाना मिलने की शिकायत पर सख्त एक्शन लेने का निर्देश दिया गया था।

वक्फ संपत्ति : केन्द्र सरकार ने पंजीकरण को लेकर दी तीन महीने की राहत



केंद्रीय मंत्री रिजिजू ने बताया कि कई क्षेत्रों से शिकायतें मिलीं कि उम्मीद पोर्टल धीमा चल रहा था या लोगों के पास आवश्यक दस्तावेज पूरे नहीं थे। उन्होंने कहा, हम चाहते हैं कि कोई भी व्यक्ति बिना परेशान हुए अपनी वक्फ संपत्ति रजिस्ट्रार करा सके। इसलिए तीन महीने तक हम किसी पर कोई सख्ती नहीं करने वाले हैं। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा था कि 6 महीने की समयसीमा के बाद सरकार तारीख नहीं बढ़ा सकती, लेकिन डिब्बनूल के पास अधिकार है कि वह आपकी स्थिति समझकर 6 महीने तक की अतिरिक्त राहत दे सकता है। इसलिए जिन्हें परेशानी हो, वे वक्फ

ट्रिब्यूनल से संपर्क करें। केंद्रीय मंत्री रिजिजू ने कहा कि केंद्र सरकार महशाला लोगों की मदद करने के लिए तैयार है, लेकिन वक्फ संशोधन कानून संसद ने पास किया है, इसलिए उसमें बदलाव केंद्र स्वयं नहीं कर सकता।

ट्रिब्यूनल से संपर्क करें। केंद्रीय मंत्री रिजिजू ने कहा कि केंद्र सरकार महशाला लोगों की मदद करने के लिए तैयार है, लेकिन वक्फ संशोधन कानून संसद ने पास किया है, इसलिए उसमें बदलाव केंद्र स्वयं नहीं कर सकता।

आने वाले सालों में हम ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में दुनिया में पहले नंबर पर होंगे

-गडकरी बोले - हमारी सरकार की प्राथमिकता है वैकल्पिक ईंधन और बायोफ्यूल

नई दिल्ली (एजेंसी)। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने गुरुवार को कहा कि देश की ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री तेजी से आगे बढ़ रही है और आने वाले सालों में यह दुनिया में पहले नंबर पर होगी। उन्होंने लोकसभा में कहा कि जब मैंने मंत्री पद संभाला था, हमारी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री दुनिया में सातवें नंबर पर थी, लेकिन अब जापान को पछड़कर दुनिया में तीसरे नंबर पर आ गई है।

भारत के ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री पर गडकरी ने कहा कि मेरे सह मंत्री हरदीप पुरी वैकल्पिक ईंधन पर काम कर रहे हैं। वहीं प्रल्हाद जोशी ग्रीन हाइड्रोजन मिशन पर काम कर रहे हैं। इससे देश के ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के आकार को बढ़ाने में मदद मिलेगी। गडकरी के मुताबिक अमेरिका 79 लाख करोड़ रुपए के साथ दुनिया का सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल बाजार है। चीन 49 लाख करोड़ के साथ दूसरे नंबर पर है। अब 22 लाख करोड़ रुपए के आकार



के साथ भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है। गडकरी ने कहा कि हमारा देश करीब 22 लाख करोड़ रुपए के जीवद्रव्य ईंधन का आयात करता है। इस कारण हमारी सरकार की प्राथमिकता वैकल्पिक ईंधन और बायोफ्यूल है। यह आयात का अच्छा विकल्प है। साथ ही लागत प्रभावी और प्रदूषण से मुक्त है, जिसका सामना आज के समय दिल्ली कर रही है।

गडकरी के मुताबिक देश में फास्ट चार्जिंग पर तेजी से काम किया जा रहा है। हमें एक ऐसे चार्जिंग सिस्टम की

जरूरत है जो ट्रक, बस, स्कूटर्स, तिपहिया और दोपहिया वाहनों के लिए उपयोगी हो। मौजूदा समय में चार्जिंग सिस्टम पर निर्यंत्र चल रही है और नए इन्वेंशन किए जा रहे हैं और अकेले दोपहिया इलेक्ट्रिक वाहन सेगमेंट में 400 स्टार्टअप काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि देश की ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार ने हाल में किए जीएसटी सुधार में कर दर में भारी कटौती की है, जिससे देश में वाहनों की बिक्री को बढ़ाने में मदद मिलेगी है।

शुक्रवार को पुतिन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करेंगे, राजघाट पर महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि देंगे और रूसी चैनल आर्टी का भारत संस्करण लांच करेंगे। शाम को रवाना होने से पहले मोदी के साथ व्यापक वार्ता होगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और उनके रूसी समकक्ष एंड्रें बेलोसोव भी सैन्य सहयोग पर चर्चा करेंगे। अमेरिकी दूतावास और यूक्रेन शांति प्रयासों के बीच यह

यात्रा रूस के लिए अलगाव कम करने का मौका है, जबकि भारत के लिए ऊर्जा सुरक्षा और हथियार आपूर्ति सुनिश्चित करने का। 2000 से चली आ रही रणनीतिक साझेदारी के 25 वर्ष पूरे होने पर यह दौरा विशेष महत्व रखता है, जो दोनों देशों के बीच विश्वास को और गहरा करेगा।

के 25 वर्ष पूरे होने पर यह दौरा विशेष महत्व रखता है, जो दोनों देशों के बीच विश्वास को और गहरा करेगा।